● वर्ष-3
● अंक-222
रायपुर, शुक्रवार
26 अप्रैल 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› गर्मियों से राहत पाने के लिए ...

लोस चुनावः देशभर की 88 सीटों पर आज वोटिंग

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव दूसरे चरण के लिए शुक्रवार 26 अप्रैल को मतदान है। मणिपुर समेत 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 88 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। मणिपुर की बाहरी मणिपुर लोकसभा सीट के 15 विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान हो चुका है, जबकि 13 अन्य विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे चरण में मतदान होना है।

इस चरण में कुल 1206 उम्मीदवार मैदान में होंगे। इनमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, शशि थरूर, लोकसभा स्पीकर और बीजेपी उम्मीदवार ओम बिरला भी शामिल हैं। इस चरण के प्रमुख उम्मीदवारों में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, भाजपा के तेजस्वी सूर्या, हेमा मालिनी, अरुण गोविल, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के भाई डी.के. सुरेश और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी हैं।

26 अप्रैल को होने वाले मतदान में 1198 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। वहीं, बाहरी मणिपुर लोकसभा के भी चार उम्मीदवारों को जोड़े तो कुल संख्या 1202 हो जाती है। बैतूल लोकसभा सीट पर आठ उम्मीदवार मैदान में हैं। जहां अब तीसरे चरण में मतदान होना है।

दूसरे दौर में जिन सीटों पर मतदान है, उनमें केरल की सभी 20, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की आठ-आठ, मध्य प्रदेश की छह, असम और बिहार की पांच-पांच, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल की तीन-तीन और जम्मू-कश्मीर और त्रिपुरा की एक-एक सीट शामिल है। इसके अलावा मणिपुर में एक भाग मणिपुर बाहरी सीट का है।

राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में आज मतदान

दूसरा चरण- 52 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे मतदान

रायपुर। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए आज 3 लोकसभा सीटों राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर के लिए मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने इसे लेकर तैयारी पूरी कर ली है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबसाहेब कंगाले ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन - 2024 के द्वितीय चरण में राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर शुक्रवार को मतदान होगा जहां 6565 मूल मतदान केन्द्र और 2 सहायक मतदान केन्द्र बनाए गए है जिनमें राजनांदगांव-2330, महासमुंद-2147 एवं कांकेर-2090 शामिल है। राजनांदगांव लोस में 15, महासमुंद में 17 एवं कांकेर 9 अभ्यिर्थी चुनावी मैदान में है। तीनों लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के24 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कल संपन्न होगा। मोहला-मानपुर, बिन्द्रानवागढ़, अंतागढ़, भानपुप्रतापपुर, कांकेर व केशकाल में सुबह 7 बजे से दोपहर को 3 बजे तक व बाकी जगहों पर सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। द्वितीय चरण में पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में मतदाताओं की संख्या में 377499 (7.69 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है। 330 संगवारी मतदान

केंद्र, 25 दिव्यांगजनों द्वारा संचालित मतदान केंद्र व 117 युवाओं द्वारा संचालित मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि द्वितीय चरण में निर्वाचन संपन्न कराने हेतु 6,567 मतदान दलों हेतु 26,268 मतदान कर्मी + रिजर्व 6,639 इस प्रकार कुल 32,907 मतदान कर्मी नियुक्त है जो शांतिपूर्ण निष्पक्ष निर्वाचन कराने हेतु मतदान केन्द्रों में पहुंच चुके है। द्वितीय चरण में 24,926 निर्वाचन ड्यूटी कर्मियों को निर्वाचन कर्तव्य प्रमाणपत्र जारी किया गया है तथा वे इसका उपयोग कर मतदान केन्द्र में ही अपना मतदान करेंगे। कांकेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में दुर्गम एवं संवेदनशील क्षेत्रों के 09 मतदान केन्द्रों में कुल 72 मतदानकर्मियों एवं महासमुंद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत गरियाबंद जिले के 02 मतदान केन्द्रों के लिए 15 मतदानकर्मियों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से मतदान केन्द्रों में निर्वाचन संपन्न कराने के लिये P-2 अर्थात दिनांक 24.04.2024 को भेजा जा चुका है। शेष 6556 मतदान दल बस के माध्यम से आज मतदान केन्द्रों के लिए रवाना हो चुके है। द्वितीय चरण के तीन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत 24 विधानसभा क्षेत्रों के सभी मतदान केन्द्रों में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष निर्वाचन हेतु सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किये गये हैं। इस चरण हेतु सुरक्षाबलों की कुल 222 कंपनियों नियोजित की गई है।

मतदान केंद्रों के बाहर दिखेगा इको टूरिज्म का नजारा, वोटर्स बाघ-भालू, जिप्सी के साथ ले सकेंगे सेल्फी

गारियाबंद। वोट के लिए लाइन लंबी होने पर भी मतदाता बोर नहीं होंगे. वो इसलिए की इस बार लोकतंत्र के महापर्व पर जिले के दो मतदान केंद्र में वोटर्स का अच्छा मनोरंजन होगा. इसके लिए उदंती सीता अभ्यारण प्रशासन ने मैनपुर और गोहरापदर केंद्र के बाहर विशेष सज्जा की है. यहां मतदाताओं को वन्य प्राणी व वनवासी कल्चर से रूबरू कराने की तैयारी की है. उदंती सीता अभ्यारण के उपनिदेशक वरुण जैन ने बताया कि मैनपुर खुर्द व गोहरापदर मतदान केंद्र के बाहर घासफूस की कुटिया, बांस के बर्तन और तीर कमान से सजावट कर इको हट का स्वरूप दिया है. इससे मतदाता आदिवासी रिवाजों से परिचित हो सकेंगे.केंद्र के बाहर वन भैंसों का पुतला व जिप्सी है, जिसे सेल्फी पॉइंट बनाया गया है. केंद्र के बाहर बाघ, भालू, तेंदुए के भेष में अभ्यारण के कर्मचारी घूमते नजर आएंगे, जो मतदाताओं का भरपूर मनोरंजन करेंगे. इसके अलावा तीरदांजी की विशेष व्यवस्था की गई है.

विरासत टैक्स मामले में कांग्रेस पर भड़के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विरासत टैक्स मामले मे कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने भारतीय समाज की उस पारिवारिक संरचना पर सीधा प्रहार किया है जो संपत्तियों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करती है और पारिवारिक रिश्तों को जोडने की मजबूत कड़ी है। श्री साय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने देश के टुकड़े किए फिर उसे जातियों मे बांटा, उसके बाद धार्मिक तुष्टीकरण करने के लिए देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का बताया। अब कांग्रेस कह रही है की आगे वो सत्ता मे आई तो कानून बना कर लोगों के मरने के बाद उनकी संपत्ति सरकार के जरिए हड़प लेगी। सैम पित्रोदा के बयान ने इसकी पुष्टि की है। यह बेहद शर्मनाक है। उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी ने बीते दिनों एक बयान में कहा था कि अगर चुनाव बाद उनकी सरकार सत्ता में आई तो एक सर्वे कराया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि किसके पास कितनी संपत्ति है और अब सैम पित्रोदा ने अमेरिकी कानून का हवाला देकर कहा है, अमेरिका में 55 फीसदी संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अमेरिका में विरासत पर कर लगता है। अगर किसी के पास 100 मिलियन डॉलर की संपत्ति है और जब वह मर जाता है तो वह केवल 45 प्रतिशत अपने बच्चों को हस्तांतरित कर सकता है जबकि 55 प्रतिशत सरकार द्वारा हड़प लिया जाता है। लेकिन भारत में रहकर अपनी पीढ़ी के लिए संपत्ति जुटाई और जब आप स्वर्गवासी हो रहे हैं तो आपको अपनी संपत्ति जनता के लिए छोडनी चाहिए। साय ने कहा है कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टिकरण मे इतनी अंधी हो गई है की वो देश के सनातन परंपरा और परिवार परंपरा पर सीधा चोट कर रही है। उनकी मंशा है की देश के लोगों की जायदाद राजसात कर उसे उनके बीच बाँट दे जिनके ज्यादा बच्चे हैं या घुसपैठिए हैं। इस देश और छत्तीसगढ़ की जनता को यह कतई स्वीकार नहीं है। साय ने कड़ी शब्दों मे कहा है कि देश के लोगों की संपत्ति विदेशी घुसपैठियों के लिए नहीं है, यहाँ के संसाधन भी रोहिंग्याओं के लिए नहीं है। यह संपत्ति-संसाधन हमारे आदिवासी, दलित, पिछड़ों, और गरीबों का है। इस पर कांग्रेस की बुरी नीयत को हम सहन नहीं करेंगे।

हार की हताशा से आंय-बांय बोल रहे हैं कांग्रेसी- साय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह सहित शीर्ष भाजपा नेताओं के छत्तीसगढ़ में हो रहे लगातार चुनावी प्रवास पर कांग्रेस द्वारा इसे भाजपा के हार का डर बताने वाले बयान पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस को अपनी हार स्पष्ट दिख रही है इसलिए वो कुछ भी आंय-बांय बोल रही है। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए श्री साय ने कहा कि कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव में 36 बड़े-बड़े वादे किये, लेकिन पूरा एक भी नहीं किया।

सीबीआई करेगी सीजीपीएससी परीक्षा 2021 की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता की जांच

रायपुर। सीजी पीएससी 2021 में हुई अनियमितता की जांच सीबीआई करेगी.केन्द्र सरकार ने इस मामले में गुरुवार को विधिवत अधिसूचना जारी कर दी है. विधानसभा चुनाव के दौरान यह मामला राज्य में काफी गरमाया हुआ था. पीएससी परीक्षा 2021 में की हुई अनियमितता को लेकर राज्य के युवाओं में बेहद आक्रोश था और इसको लेकर युवा सड़कों पर उतर आए थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव के दौरान युवाओं के आक्रोश को देखते हुए इस मामले की जांच

केन्द्र सरकार ने जारी की अधिसूचना

कराने और दोषी लोगों के विरूद्ध कार्यवाही की गारंटी दी थी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की राज्य के युवाओं से की गई यह गारंटी भी अब सीबीआई के सुपुर्द होते ही पूरी हो गई है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में नवगठित सरकार ने भी पीएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ी और युवाओं की शिकायत के मद्देनजर 3 जनवरी 2024 कैबिनेट बैठक में इस मामले की सीबीआई से जांच कराने का निर्णय लिया था. राज्य सरकार की सहमति मिलने के बाद केन्द्र सरकार ने जांच के लिए अधिसूचना जारी कर यह मामला अब सीबीआई के सुपुर्द कर दिया है. यहां यह उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा 2021 में राज्य के 12 विभागों के लिए 170 पदों पर भर्ती के लिए चयन सूची जारी की गई थी.

प्रमुख समाचार

कई राज्यों में प्रचंड गर्मी और लू का पूर्वानुमानः आईएमडी

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को होगी। चुनाव आयोग ने भीषण गर्मी के बीच शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव तैयारियां की हैं। हालांकि, लगातार बढ़ रहा तापमान आयोग के साथ-साथ लोगों के भी पसीने छुड़ा रहा है। मौसम विभाग ने आगाह किया है कि 26 अप्रैल को मतदान के लिए घरों से निकलने पर जनता को चिलचिलाती धूप का सामना करना पड़ेगा। गुरुवार को मौसम विभाग की तरफ से जारी अलर्ट के मुताबिक अगले पांच दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गर्म हवाएं और लू चलने की आशंका है। आईएमडी ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लिए रेड अलर्ट, जबकि बिहार और कर्नाटक के कुछ हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक 27-29 अप्रैल के दौरान ओडिशा में रातें गर्म होंगी। मौसम विभाग के मुताबिक रात का उच्च तापमान अधिक खतरनाक माना जाता है, क्योंकि ऐसे हालात में शरीर को ठंडा होने का मौका नहीं मिलता।

किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष साहू ने दिया पार्टी से इस्तीफा

रायपुर। छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास साहू ने दिया आज इस्तीफा दे दिया है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को भेजे अपने इस्तीफे में उन्होने लिखा है कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना जिस मूल्यों के आधार पर हुई हैं, आज कांग्रेस पार्टी उससे पूरी तरीके से भटक चुकी हैं। जिसका सबसे बड़ा प्रमाण हैं इस देश के बहु संख्यक हिन्दुओं की भावनाओं को कुचलकर हम सब के आराध्य भगवान राम जी की जन्म स्थली अयोध्या में उसके मूर्ति स्थापना के आमंत्रण को ठुकरा देना, देश की एकता को तार तार करने वाले कश्मीर में लगाए गए धारा 370 के खत्म होने का विरोध करना, अल्पसंख्यक को खुश करने के लिए बहुसंख्यक हिन्दुओं को अपमानित करना उसके अलावा वोटों की राजनीति के लिए किसानों की हितों की बात करना पर जमीनी धरातल पर प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक किसानों एवं किसान कांग्रेस के पदाधिकारियों की उपेक्षा इन सारी बातों के कारण मैंने किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का फैसला लिया हैं।

आज शाह बेमेतरा में, खडगे 28 को जांजगीर चांपा व राहुल 29 को बिलासपुर करेंगे चुनावी सभा

रायपुर। छत्तीसगढ़ में जहां कल दूसरे चरण का मतदान होने जा रहा हैं वहीं तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होनी है। इसके लिए भाजपा और कांग्रेस प्रचार-प्रसार में जोरशोर से लगे हुए है। तीसरे चरण के लिए भाजपा की ओर से केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, शुक्रवार को बेमेतरा में चुनावी सभा को संबोधित करने आ रहे है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे 28 अप्रैल को जांजगीर-चांपा व कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी 29 अप्रैल को बिलासपुर आ रहे है जहां वे जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 26 अप्रैल की सुबह राजधानी रायपुर पहुंचेंगे जहां से वे दुर्ग लोकसभा सीट के बेमेतरा जिले के दौरे पर निकल जाएंगे जहां वे दोपहर को 12 बजे बेसिक स्कूल मैदान में आयाजित चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे इस लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए पहली बार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। वे 28 अप्रैल को जांजगीर चांपा में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी शिव कुमार डहरिया के लिए वोट मांगेगे।

व्हाट्सएप के जरिए दाखिल और सूचीबद्ध केसों की जानकारी देगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75वें वर्ष में न्याय को सर्वसुलभ बनाने की दिशा में एक नई पहल करते हुए वकीलों को खास तोहफा दिया है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने इस दिशा में गुरुवार (25 अप्रैल) को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं के इस्तेमाल से एकीकृत व्हाट्सएप सेवा की शुरुआत करने की घोषणा की। इससे वकीलों को केस दाखिल करने से लेकर कई अन्य सूचनाएं उनके मोबाइल पर ही व्हाट्सएप के जरिए ही मिल सकेंगी। नई सेवा की घोषणा करते हुए चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, स्थापना के 75वें वर्ष में सुप्रीम कोर्ट ने न्याय तक पहुंच को मजबूत करने के लिए एक नई पहल शुरू की है। अब व्हाट्सएप मैसेजिंग को आईसीटी सेवाओं के साथ एकीकृत किया जा रहा है। इससे वकीलों को मामलों के दाखिल होने की जानकारी उनके मोबाइल पर स्वतः व्हाट्सएप संदेश से प्राप्त हो सकेंगे। इसके अलावा बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों को कॉजलिस्ट प्रकाशित होने पर भी सूचना मिल सकेंगी।

राज्यसभा सांसद के तौर पर राजा देवेंद्र प्रताप सिंह ने ली शपथ

रायगढ़/रायपुर। छत्तीसगढ़ में चल रहे लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के बीच राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद राजा देवेंद्र प्रताप सिंह ने गुरुवार को दिल्ली में शपथ ग्रहण किया. राज्यसभा के सभापति व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. शपथ ग्रहण के अगले ही दिन शुक्रवार से सांसद फिर से प्रदेश में लोकसभा चुनाव की प्रचार की बागडोर संभाल लेंगे. विदित हो कि भारतीय जनता पार्टी ने सांसद राजा देवेंद्र प्रताप सिंह को पूरे प्रदेश में स्टार प्रचार बनाया है, साथ ही राज परिवारों को साधने की ज़िम्मेदारी सौंपी है. अपने प्रवास के दौरान राजा देवेंद्र प्रताप सिंह को पार्टी कैडर को मजबूत करने के लिए नुक्कड़ सभा, बैठक, आमसभा करने की जिम्मेदारी दी है. बीते 1 महीने से राजा देवेंद्र प्रताप सिंह सरगुजा से लेकर बस्तर तक लगातार भाजपा के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, साथ ही वह प्रत्याशियों के साथ दुर्गम क्षेत्रों में भी जा रहे हैं.

चुनाव में चले सियासी तीर, कांग्रेस के घोषणापत्र पर आक्रामक हुई भाजपा

मृत्युंजय दीक्षित

लोकसभा चुनावों के प्रथम चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। दूसरे चरण का प्रचार चरम पर है। प्रथम चरण के चुनावों में भाजपा नेतृत्व राम लहर और मोदी के करिश्माई नेतृत्व के बल पर अबकी बार चार सौ पार के नारे के साथ आगे बढ़ रहा था और चुनावी रैलियों में, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ एक बार फिर मोदी सरकार की बात की जा रही थी। भाजपा नेतृत्व अभी तक विपक्ष को परिवारवाद व उनके शासनकाल में किए गये अथाह भ्रष्टाचार और घोटालों की बात करके घेर रहा था लेकिन उसके मुस्लिम तुष्टिकरण पर सीधा प्रहार नहीं कर रहा था किन्तु कांग्रेस के चुनावी घोषणापत्र, राहुल गांधी व विपक्ष के नेताओं के कुछ आपत्तिजनक बयानों के बाद नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी भारतीय जनता पार्टी अब कांग्रेस तथा विरोधी दलों के घोर मुस्लिम तुष्टिकरण या कहें कि हिन्दू घृणा के खिलाफ बहुत आक्रामक हो गयी है। मोर्चा स्वयं नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस के समय में प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह के भाषण और कांग्रेस के घोषणापत्र में किए गए वादों पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने स्वयं खोला।

भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में पहली बार विरोधी दल कांग्रेस के घोषणपत्र को ही आधार बनाकर उस पर इतना तीखा हमला बोला गया है। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस और उसके साथी तिलमिला गए हैं और वह मुख्य धारा तथा सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी पर अर्मायदित शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री मोदी की शिकायत लेकर चुनाव आयोग भी पहुंचा है उधर भाजपा का प्रतिनिधि मंडल भी राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंच गया है।

प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के सभी बड़े नेता कांग्रेस के मुस्लिम प्रेम पर एक के बाद एक तीखा प्रहार कर रहे हैं जिससे कांग्रेस तिलमिला गई है। प्रधानमंत्री मोदी एक के बाद एक कांग्रेस की सरकारों में हुए हिन्दू विरोधी घटनाओं, निर्णयों, विवादों को उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले राजस्थान की एक जनसभा में कहा कि, कांग्रेस की नजर आम लोगों की मेहनत की कमाई पर है, प्रापर्टी पर है महिलाओं के मंगलसूत्र पर है। कांग्रेस ने इरादा जाहिर कर दिया है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो लोगो के घरों, प्रापर्टी और गहनों का सर्वे कराएगी फिर लोगों की कमाई कांग्रेस के पंजे में होगी। कांग्रेस की नजर देश की महिलाओं के गहनों पर है, माताओं- बहनों के मंगल सूत्र पर है वो उसे छीन लेना चाहती है। कांग्रेस के चुनाव घोषणापत्र में उसके इरादे साफ जाहिर हो रहे हैं। अगर कांग्रेस की सरकार आई तो लोगो के बैंक एकाउंट में झांकेगी, लॉकर खंगालेगी, जमीन-जायदाद का पता लगायेगी और फिर सब कुछ छीनकर उसे घुसपैठियों और ज्यादा बच्चे वालों में बांट देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस यह संपत्ति उन लोगों को बांटेगी जिन्हें मनमोहन सरकार ने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इस बयान ने चुनाव के मैदान में तूफ़ान आ गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को धार्मिक आधार पर मुस्लिम आरक्षण को लेकर भी घेरा है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में 2004 से 2010 के बीच मुसलमानों को दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों का हिस्सा काटकर उसमें से ही विशेष आरक्षण देने का भरसक प्रयास किया किंतु न्यायपालिका के हस्तक्षेप से कांग्रेस का यह विकृत पायलट प्रोजेक्ट लागू नहीं हो सका जबकि अब यही कांग्रेस भारत का संविधान बदलकर दलित, पिछड़ों, अतिपिछड़ों के अधिकारों में कटौती करके मुस्लिम आरक्षण देने की बात कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने ही बयानों से फंस जाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फुल टॉस गेंद फेंककर चुनाव के मैदान में चौके-छक्के लगाने का अवसर दे बैठते हैं। राहुल गांधी ने कांग्रेस का घोषणापत्र जारी हो जाने के बाद एक जनसभा में कहा कि, सत्ता में आने पर वह देश का एक्सरे कर देंगे। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पिछड़े, दलित, आदिवासी, गरीब, सामान्य वर्ग के लोगों को पता चल जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम वित्त और संस्थागत सर्वे करेंगे और यह पता लगायेंगे कि हिंदुस्थान का धन किसके हाथों में है और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। इस बयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रन बनाने का सुनहरा अवसर दे दिया और वे हिंदुत्व को लेकर आक्रमक हो गए। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो अभी तक केवल अयोध्या, मथुरा, काशी और विरोधी दलों के माफिया प्रेम व कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे वो भी बोल पड़े, कांग्रेस देश में शरिया कानून लागू करना चाहती है लेकिन यह देश संविधान से ही चलेगा शरिया से नहीं।

दूसरे चरण के मतदान पर नक्सलियों का साया बंद के आह्वान का दिख रहा छिटपुट असर

भानुप्रतापपुर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल यानी 26 अप्रैल को होना है। जिसमें छत्तीसगढ़ की तीन लोकसभा सीटों कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव में मतदान होगा। वहीं मतदान के एक दिन पहले नक्सलियों ने पूरे बस्तर संभाग में बंद का आह्वान किया है। बता दें कि कांकेर जिले के हापाटोला के कलपर जंगल में 16 अप्रैल को हुई पुलिस-नक्सली मुठभेड़ में जवानों ने 29 नक्सलियों को मार गिराया था। इस मुठभेड़ के बाद नक्सली बौखलाए हुए हैं, इसके विरोध में आज बंद का आह्वान किया है। इसका थोड़ा असर कांकेर जिले के कुछ इलाकों में दिख रहा है। वहीं प्रशासन सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से तैयार है। सभी पुलिस चौकियों को अलर्ट कर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है।

जानकारी के मुताबिक, पखांजूर बांदे से भानुप्रतापपुर तक आवागमन बंद है। इस मार्ग पर यात्री वाहन नहीं चल रहे हैं। हालांकि, वाहनों को चुनाव आयोग द्वारा अधिग्रहित करने के बाद पिछले दो दिनों से यात्री वाहनों की सड़क पर कमी थी पर आज पूरी तरह से यात्री वाहनों का चलना बंद है। दुर्गुकोंदल,बड़गांव जैसे क्षेत्र में बाजार अभी तक नहीं खुले हैं। इस क्षेत्र में संचालित होने वाली लौह अयस्क की खदानें में भी कार्य बंद कर दिया गया है। इससे कहा जा सकता है कि बंद का असर देखा जा रहा है। वहीं भानुप्रतापपुर का बाजार खुला हुआ है और आवागमन सामान्य दिनों की तरह चालू है। अंतागढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश बढ़ाई ने बताया कि सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं और सभी थाना चौकी को अलर्ट किया गया है। वहीं जिला कलेक्टर अभिजीत सिंह ने कहा कि हमने व्यापारियों और कारोबारियों से बात की है बंद का असर इन क्षेत्रों में नहीं पड़ेगा।

सर्चिंग में निकली थी टीम, अचानक चली गोली, डीआरजी जवान की हुई मौत और एक घायल

जगदलपुर। दंतेवाड़ा जिले में पुलिस जवानों को सूचना मिली थी कि भारी संख्या में हथियाबंद नक्सली मीटिंग कर रहे हैं। सूचना के आधार पर दंतेवाड़ा जिले से एक टीम 24 अप्रैल की रात को निकली थी, लेकिन उसी टीम के एक जवान की बंदूक से गोली चलने के कारण एक डीआरजी जवान की मौत हो गई। वहीं, एक अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि दंतेवाड़ा-नारायणपुर के सीमावर्ती इलाके में नक्सल गश्त पर निकली सर्चिंग के दौरान दुर्घटनावश एक जवान के बंदूक से गोली चलने से डीआरजी दंतेवाड़ा के एक जवान की मृत्यु हो गई, जबकि एक जवान घायल है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि जिला दंतेवाड़ा थाना बारसूर क्षेत्र के अंतर्गत हांदावाडा, हितावड़ा क्षेत्र में बंदूकधारी नक्सलियों के मीटिंग के साथ ही भारी संख्या में नक्सलियों के जमा होने की सूचना पर 24 अप्रैल को दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर के सीमावर्ती क्षेत्र में डीआरजी एवं बस्तर फाइटर्स दंतेवाड़ा की संयुक्त टीम नक्सल गश्त सर्चिंग अभियान में निकली थी। 24 अप्रैल की रात को नक्सल गश्त सर्चिंग के दौरान लगभग 11 बजे गलती से गोली चलने से डीआरजी दंतेवाड़ा के आरक्षक जोगराज कर्मा व आरक्षक परसूराम अलामी घायल हो गए। रेस्क्यू के दौरान घायल आरक्षक जोगराज कर्मा की शरीर से अधिक खून बह जाने से मृत्यु हो गई एवं घायल आरक्षक परसूराम अलामी का प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज हेतु एयरलिफ्ट कर रायपुर रवाना किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले को लेकर जांच की जा रही है।

नक्सलियों के खिलाफ सघन अभियान जल्द करें सरेंडर : बीजापुर कलेक्टर

बीजापुर। नक्सलियों के खिलाफ लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बस्तर संभाग के सभी नक्सल प्रभावित जिले में नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस वजह से नक्सली बौखलाए हुए हैं और निर्दोष लोगों को क्षति पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में बीजापुर कलेक्टर अनुराग पांडेय ने नक्सलियों को माओवादी विचार धारा और हथियार छोड़कर आत्मसर्मपण करने को कहा है।

बीजापुर कलेक्टर अनुराग पांडेय ने कहा, अभी भी समय है। विदेशी विचार धारा को छोड़ कर अपने और आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए आत्मसर्मपण करें। नई पुनर्वास नीति के तहत उनका पुर्नवास किया जाएगा। जो लोग पहले आत्मसर्मपण किए हैं, आज वे लोग मुख्य धारा में जुड़कर बेहतर जीवन जी रहे हैं। अपने परिवार अपने बच्चों के सुखद भविष्य की ओर अग्रसर हैं। ये विकास विरोधी तत्व बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास से ग्रामीणों को दूर रखकर अपने नापाक मसूंबो की पूर्ति के लिए सुनियोजित ढंग से आतंक कर रहे हैं। इनका अंत तय है।

कलेक्टर अनुराग पांडेय ने कहा आज जो शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास से ग्रामीणों को दूर रख कर हैं, वह स्वयं तो उच्च शिक्षित हैं। लैपटॉप, कम्प्यूटर और उच्च तकनीकी ज्ञान रखते हैं। लेकिन उन्हीं लोगों ने बीजापुर की एक पीढ़ी को शिक्षा से वंचित करने का पाप किया है। नक्सलियों के प्रेसनोट में शुद्ध हिन्दी की कमी, बिना किसी व्याकरण और वर्तनी त्रुटि को देखा जा सकता है, जो किसी शहरी क्षेत्र में बना दिखता है।

जिस तरह उनके लगाए आईईडी ब्लास्ट से बीजापुर के बेकसूर और मासूम ग्रामीण आदिवासी व पुलिसकर्मी मारे जा रहे हैं, वह घोर निंदनीय है। इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। अरबन नक्सलियों के खिलाफ भी कार्रवाई तेज किए जाएंगे।

कलेक्टर अनुराग पांडेय ने कहा बीजापुर की भोली-भाली जनता इनके नापाक मंसूबो को समझ चुकी है और विकास की ओर अपना कदम बढ़ा रही है। इसका ताजा उदाहरण दो बार नक्सली बंद के आह्वान को आम जनता ने सिरे से नकार दिया। लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा निर्वाचन 2024 में भी लोग बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की।

जगदलपुर में धमाके की आवाज के साथ भूकंप के हल्के झटके से घरों से बाहर निकले लोग

बस्तर संभाग भूकंप के लिए सेफ जोन में आता है

जगदलपुर। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के पूर्वी क्षेत्र आमागुड़ा, कुम्हारपारा, पथरागुड़ा के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों आड़ावाल, सेमरा, करकापाल में बुधवार देर शाम लगभग 8.45 बजे जोरदार धमाके की आवाज के साथ भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए, तीन से चार सेकंड तक भूकंप सक्रिय रहा। लोग डर से घरों से बाहर निकल आए थे। भूकंप के झटके से नुकसान की कोई जानकारी नहीं है। भूकंप की जानकारी के लिए भारत मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर केवरिष्ठ मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने भी बताया कि उन्हें भी बस्तर क्षेत्र में भूकंप की सूचना मिली है। उन्होने बताया कि नेशनल सेंटर फार सिस्समोलाजी के अनुसार भूकंप का केंद्र जगदलपुर से 2 किमी दूर उत्तर पूर्व में 5 किमी गहराई पर था। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.6 आंकी गई है।

जगदलपुर निवासी किशोर पानीग्राही जो स्वयं एक जियोलाजिस्ट भी हैं उन्होने बताया कि तेज धमाके की आवाज सुनकर ऐसा लगा जैसे कोई विस्फोट हुआ हो, घर के बाहर आकर देखने पर आस-पास के लोगों ने भी धमाके की आवाज सुनी और कुछ सेकेंड के झटके महसूस किये। उन्होने बताया कि बस्तर संभाग का इलाका भूकंप के लिए सेफ जोन में आता है, यहां अधिक तीव्रता का भूकंप आने की संभावना नही है। उन्होने बताया कि बस्तर में इसके पहले चार साल पूर्व भूकंप के इसी तरह के हल्के कंपन्न महसूस किया गया था, तब भूकंप का केंद्र बस्तर और सुकमा जिला तथा पड़ोसी राज्य ओड़िशा का मलकानगिरी जिला था। उस समय भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 4.2 मापी गई थी।

बिलासपुर लोकसभा सीट के चुनावी मैदान में 37 उम्मीदवार

बिलासपुर। बिलासपुर नामांकन दाखिल होने, स्क्रुटनी और नाम वापसी के बाद मैदान में 37 उम्मीदवार बचे हैं। 37 उम्मीदवारों में देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के साथ ही क्षेत्रीय पार्टी के प्रत्याशी सहित निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव में अपना भाग्य आजमाएंगे। ऐसे में 37 उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने से निर्वाचन आयोग को अतिरिक्त बैलट यूनिट लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। अब निर्वाचन आयोग ने 37 उम्मीदवारों के लिए तीन बैलट यूनिट लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए आयोग ने भारत निर्वाचन आयोग से संपर्क कर लगभग 1800 बैलेट यूनिट मंगाई है। बैलेट यूनिट आने के बाद फर्स्ट लेवल चेकिंग 26 अप्रैल से 28 अप्रैल तक की जाएगी। ये काम लगातार तीन दिनों तक चलेगा।

1800 बैलेट यूनिट की पड़ेगी जरूरत

इसके बाद 6 मई को वोटिंग के लिए ईवीएम रवाना किए जाएंगे। बिलासपुर लोकसभा सीट में 37 उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने की वजह से इलेक्शन कमिशन बिलासपुर को तीन नई बैलेट यूनिट लगानी पड़ेगी। इससे पहले 2014 और 2019 में दो बैलेट यूनिट लगाई गई थी। इसलिए चुनाव संपन्न कराने के लिए एक्स्ट्रा बैलेट यूनिट की जरूरत होगी। बिलासपुर में 1684 मतदान केंद्रों के लिए इलेक्शन कमीशन 1800 बैलेट यूनिट मंगाई है जिन्हें जल्द ही वोटिंग के लिए तैयार कर लिया जाएगा।

हर लोकसभा चुनाव में बढ़ती गई बैलेट यूनिट

बिलासपुर लोकसभा सीट में चुनाव लड़ने उम्मीदवारों की संख्या बढ़ती जा रही है। 2004 और 2009 में जहां इलेक्शन कमीशन ने एक बैलेट यूनिट से चुनाव कराया था, वहीं 2014 और 2019 में दो बैलेट यूनिट लगानी पड़ी थी। 2014 में 19 उम्मीदवारों ने अपना भाग्य आजमाया था इसी तरह 2019 में 25 उम्मीदवारों ने चुनावी मैदान में कदम रखा।

इस चुनाव में पिछले चार चुनाव की तरह बीजेपी ने सीट पर कब्जा बनाए रखा, लेकिन इसके बाद भी उम्मीदवारों की संख्या बढ़ती जा रही है। 2024 के चुनाव में 37 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। 2014 और 2019 में दो बैलेट यूनिट लगाए गए थे। लेकिन इस बार 2024 में तीन बैलेट यूनिट लगाई जाएगी।

निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने वाले 4 कर्मचारी निलंबित

बालोद। बालोद जिले में निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने वाले चार कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रकांत कौशिक ने निलंबन आदेश जारी किया है। निलंबन अवधि के दौरान चारों कर्मचारियों को जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता रहेगी। मतदान के दौरान किसी भी अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने के मूड में प्रशासन दिख रही है। कड़ाई से निर्वाचन ड्यूटी में मॉनिटरिंग की जा रही है। निलंबित कर्मचारियों में ग्राम पीपरछेड़ी के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 देवनारायण राणा, डौंडीलोहारा तहसीलदार कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड-2 मिलाप सिंह रावटे, तहसीलदार कार्यालय डौंडीलोहारा में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 वीरेंद्र कुमार उइके और ग्राम नारागांव के हाईस्कूल में पदस्थ भृत्य पुष्पेंद्र सोनकर हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी आदेश में कहा है कि उक्त चारों की ड्यूटी लोकसभा आम निर्वाचन-2024 के लिए सामग्री वितरण-वापसी में लगाई गई थी। इनके द्वारा निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने के कारण, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा-13 (सीसी) एवं धारा 28 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 एवं छग सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के उपनियम (1), (2), (3) एवं छग सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम- 09 (02) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

शत प्रतिशत मतदान : चैंबर ऑफ कॉमर्स की विशेष पहल

गौरेला पेंड्रा मरवाही। लोकतंत्र के महापर्व में जिले में खासकर शहरी क्षेत्रों में शत प्रतिशत मतदान के लिए जीपीएम चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा विशेष पहल की जा रही है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी लीना कमलेश मंडावी की अपील पर लोकसभा निर्वाचन के तीसरे चरण के मतदान दिवस सात मई को अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने व्यापारिक प्रतिष्ठानों द्वारा मतदाता ग्राहकों को विभिन्न सामानों की खरीदी पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। जीपीएम चेंबर आफ कॉमर्स के अध्यक्ष मनीष केशरी ने कहा है कि अधिक से अधिक मतदाताओं को वोट डालने हेतु प्रेरित करने के लिए टॉकिजों-सिनेमा घर के मालिकों द्वारा वोट डालने के बाद उंगली में अमिट स्याही का निशान दिखाने पर टिकटों में एक सप्ताह तक 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। साथ ही मतदाता जागरूकता के उद्देश्य से कान्हा स्वीट्स गौरेला ने भी मिष्ठान खरीदी पर 10 प्रतिशत छूट देने की सहमति व्यक्त की है। इसी तरह विभिन्न प्रतिष्ठानों द्वारा सामान खरीदी पर विशेष छूट देने के संबंध में योजना तैयार कर रहे हैं।

तालाब किनारे स्थापित हनुमान जी की मूर्ति के साथ छेड़छाड़

जांजगीर चांपा। नवागढ़ थाना क्षेत्र के कटौद गांव में तालाब के किनारे स्थापित हनुमान जी की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ की गई। मूर्ति के सामने पत्थर और मिट्टी रखी गई है। वहीं, तोरण से सजे हुए पंडाल को तोड़कर सड़क के किनारे फेंक दिया गया है। मामले को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। वहीं, सीसीटीवी कैमरे में 10 से 15 युवक रात में घूमते हुए दिख रहे हैं। जानकारी के अनुसार, कटौद गांव में रात 10 बजे 10 से 15 युवक गांव में घूमते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। वे सभी हिंदू देवी-देवताओं को गाली दे रहे हैं। वहीं, हाथों में डंडा और हथियार भी लिए हुए हैं। गांव के तालाब के किनारे हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई है। मूर्ति के सामने उपद्रवियों ने पत्थर और मिट्टी रखकर हनुमान जी की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ करते हुए तोड़ने की कोशिश की। हुनामान जयंती में सजाए गए तोरण को भी निकालकर सड़क पर फेंक दिया। गुरुवार की सुबह को पता चलने पर बजरंग दल, सर्व हिंदू संगठन और ग्रामीणों की भीड़ मूर्ति के पास उमड़ पड़ी और अक्रोशित होकर सड़क चक्का जाम शुरू किया।

हादसे में बाइक सवार आरक्षक गंभीर रूप से घायल

जगदलपुर। शहर के लालबाग तिराहे के पास बुधवार की रात को एक तेज रफ्तार कार व बाइक सवार के बीच भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार आरक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया। आरक्षक के सिर में गंभीर चोट लग गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस टीम और परिजन भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बताया कि रक्षित केंद्र में पदस्थ सुनील सिदार अपनी बाइक पर सवार होकर लालबाग की ओर जा रहे थे, तभी अचानक से लालबाग तिराहे पर सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार टक्कर हो गई। घटना के तत्काल बाद घायल को पहले महारानी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि आरक्षक के सिर में गंभीर चोट लगी है। इसके बाद उन्हें मेडिकल कालेज डिमरापाल रेफर कर दिया गया। जहां उनका इलाज चल रहा है।

पाली की देशी शराब दुकान से 2.93 लाख की लूट

कोरबा। कोरबा के पाली थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है। यहां देशी शराब की दुकान में नकाबपोश बदमाशों ने धावा बोल दिया। फिल्मी अंदाज में सेल्समेन की कनपटी पर बंदूक रखकर बदमाश दो लाख 93 हजार नगदी लूटकर फरार हो गए। पुलिस नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश करती रही, लेकिन उनका सुराग नहीं मिला है। जानकारी के मुताबिक, घटना रात करीब 9.45 बजे की है। कर्मचारी जब दुकान बंद करने की तैयारी में थे, तभी बाइक पर सवार होकर तीन युवक देशी शराब दुकान के सामने पहुंचे। तीनों युवक का चेहरा गमछे से ढंका हुआ था। वे दनदनाते हुए सीधे शराब दुकान के भीतर जा घुसे। इनमें से एक दुकान के दरवाजे में खड़ा था, जबकि एक बदमाश ने कर्मचारी की कनपटी पर बंदूक रख दी। वहीं तीसरा रुपयों को समेटने में लगा रहा। कुछ ही मिनट के भीतर नकाबपोश बदमाश दो लाख 93 हजार रुपए नगदी को समेट कर फरार हो गए। उनके जाते ही कर्मचारियों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। इस वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस भी हरकत में आ गई।

कैप्सूल वाहन ने मारुति वैन को पीछे से मारी जोरदार टक्कर

सक्ती। सक्ति जिले के अमलीडीह और भेड़ीकोना के बीच पुल के ऊपर कैप्सूल वाहन ने ओमनी वैन को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। ओमनी वैन में पिता-पुत्र सवार थे जो कि रामनवमी मेले में जूस बेचकर घर जा रहे थे। वहीं, हादसे में बेटे की मौत हुई है। पिता गंभीर रूप से घायल हुआ है। जिसे बिलासपुर रेफर किया गया है। मृतक युवक के परिजनों और ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग की लेकर पुल के ऊपर शव को रखकर चक्का जाम किया ही। मौके पर पुलिस बल तैनात है और परिजनों को समझाकर जाम खुलवाया। जानकारी के मुताबिक, ग्राम लालीमाटी का रहने वाला सुरेश कुमार खुटे अपने पुत्र रूपेंद्र खूटे के साथ ओमनी वैन में बैठकर डभरा में चल रहे रामनवमी मेले में जूस बेचने आया हुआ था। जिसके बाद वह बुधवार की रात्रि अपने बेटे रूपेंद्र को लेकर घर जाने के लिए निकला। तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार कैप्सूल वाहन के चालक ने ओमनी वेन को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। जिससे ओमनी वेन की परखच्चे उड़ गए।

मलखंभ खिलाड़ी दे रहे अनोखे अंदाज में लोकतंत्र के महापर्व का संदेश

जांजगीर चांपा। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वोटरों को मतदान के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच जांजगीर चांपा में स्वीप टीम ने मलखम्भ के जरिए लोगों को वोटिंग के लिए जागरूक किया। साथ ही निष्पक्ष मतदान की अपील की। इसके बाद स्वीप टीम ने लोगों को मतदान के लिए शपथ भी दिलाई।

दरअसल, जांजगीर चाम्पा में मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने का नया तरीका अपनाया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर के निर्देश पर गुरुवार को पामगढ़ के डीएवी स्कूल परिसर में मतदाता जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मलखम्भ के खिलाड़ियों ने अपनी कला का

प्रदर्शन करते हुए लोगों से मतदान की अपील की। इसके बाद टीम ने मानव श्रृंखला बना कर एकता का सन्देश भी दिया।

जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आकाश छिकारा के निर्देश से जिले में शतप्रतिशत मतदान का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बुजुर्ग, दिव्यांग, युवा, थर्ड जेंडर और महिला सहित अन्य मतदाताओं के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर शत प्रतिशत मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके तहत स्वीप मलखंभ का आयोजन गुरुवार को पामगढ़ में किया गया। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत सीईओ ने मतदाताओं को लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए निष्पक्ष मतदान की शपथ दिलाई।

गरियाबंद जिले में चुनाव की सभी तैयारियां पूर्ण

गरियाबंद। कलेक्टर दीपक अग्रवाल के मार्गदर्शन में जिले में लोकसभा निर्वाचन 2024 की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 26 अप्रैल को जिले के 573 मतदान केंद्रों में मतदान होगा। इसमें 4 लाख 60 हजार 139 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। कल दूसरे चरण के होने वाले मतदान के लिए गरियाबंद के कृषि उपज मंडी परिसर में मतदान दलों को मतदान सामग्री वितरित कर अपने-अपने पोलिंग बूथों के लिए रवाना किया गया।

कलेक्टर अग्रवाल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम कांबले ने गुरुवार सुबह विधानसभा क्षेत्र बिन्द्रानवागढ़ के दूरस्थ मतदान केंद्रों के अंतर्गत रूट क्रमांक 27 के मतदान दलों को शुभकामनाओं सहित सर्वप्रथम रवाना किया। उन्होंने मतदान दलों और संगवारी मतदान केंद्र के महिला मतदान कर्मियों से मुलाकात कर उन्हें सफलतापूर्वक अपने जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए शुभकामनाएं दी।

शादी के तीसरे दिन दुल्हन ने लगाई फांसी

बलौदाबाजार। नई नवेली दुल्हन ने शादी के तीसरे दिन ही पंखे के हुक पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बेटी के मौत को लगे लगाने की वारदात से परिवार को गहरा सदमा लगा है। सुहेला पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार यह मामला पलारी के फुंडरडीह गांव का है जहां एक युवती ने शादी के तीसरे दिन खुदकुशी कर जीवन लीला समाप्त कर ली। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। सुहेला थाना पुलिस ने बताया कि क्षेत्र की रहने वाली नई नवेली दुल्हन तनुजा ध्रुव (25) ने अपने मायके जाकर पंखे के हुक पर फांसी लटककर खुदकुशी कर ली।

पता चलने पर परिजन उसे पलारी सामुदायिक केंद्र ले गए जहां डॉक्टरों ने उसकी मौत की पुष्टि की। बताया कि मृतका की शादी के दूसरे ही दिन मायके आई थी। उसकी शादी 21 अप्रैल को रावल हथबंद गांव में रहने वाले अजय से हुई थी। दूसरे ही दिन मायके वाले चौथिया की रस्म में अपनी बेटी को लेकर मायके आए थे। इसके बाद युवती ने अपने कमरे में फांसी लगा ली। किन करणों से युवती ने सुसाइड की है अभी तक पता नहीं चला है।

पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है।

ससुराल से मायके लौटी दुल्हन ने मौत से पहले अपने पति को फोन लगाया था, लेकिन बात नहीं हुई थी। बताया जा रहा है कि 23 तारीख की शाम दुल्हन अपने मायके पहुंची तो अपने पति को वॉट्सएप में मैसेज कर घर पहुंचने की सूचना भी दी और देर रात दूल्हे को फोन भी लगाया था, लेकिन दूल्हे के सो जाने के कारण उससे बात नहीं हो पाई और दूसरे दिन सुबह 12 बजे फांसी पर लटक कर उसने आत्महत्या कर ली। आखिर वह अपने पति को क्या बताना चाहती थी ये सवाल एक पहेली बनी हुई है।

संक्षिप्त समाचार

राज्य में सीबीआई के लिये खुले दरवाजे राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना

रायपुर। राज्य सरकार ने सीबीआई के प्रवेश पर लगे बैन को समाप्त करते हुए उसके प्रवेश की अधिसूचना जारी कर दी है। अब सीबीआई हर मुद्दे पर जांच कर सकती है। सबसे पहले बिरनपुर हत्याकांड और सीजी पीएससी घोटाले को लेकर जांच-पड़ताल की जाएगी। उल्लेखनीय है कि, सीबीआई के प्रवेश पर रोक से पहले यहां सीबीआई जग्गी हत्याकांड, बिलासपुर के पत्रकार सुशील पाठक और छुरा के उमेश राजपूत की हत्या, एसईसीएल कोल घोटाला, आईएएस बीएल अग्रवाल रिश्वत कांड, भिलाई का मैगनीज कांड और एक पूर्व मंत्री की कथित अश्लील सीडी कांड की जांच में शामिल थी। राज्य में पिछले 18 सालों के दौरान सीबीआई की ओर से आधा दर्जन मामलों की जांच की जा चुकी है। लोकसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार का बड़ा कदम माना जा सकता है। प्रदेश की एजेंसियों को जांच का जिम्मा दिया गया था। जरूरत पडने पर सरकार विशेष जांच दल गठित कर देगी, जो अफसरों के साथ न्यायिक अधिकारियों के नेतृत्व में बनाए जा सकते हैं। सीबीआई गठन के कानून में ही राज्यों से सहमति लेने का प्रावधान है।

26 गांव का साप्ताहिक बाजार आज नहीं लगेंगा

कांकेर। कांकेर लोकसभा चुनाव के लिए 26 अप्रैल को मतदान किया जाएगा। मतदान की प्रक्रिया प्रभावित न हो इसके लिए जिले में मतदान के दिन 26 अप्रैल को लगने वाले साप्ताहिक बाजारों की तिथि व दिन में परिवर्तन किया गया है। जिला प्रशासन व चुनाव आयोग के इस आदेश के बाद 26 गांव में लगने वाले साप्ताहिक बाजार मतदान से एक दिन पहले गुरुवार को 16 गांव का साप्ताहिक बाजार लगा वहीं 6 गांव के साप्ताहिक बाजार एक दिन बाद 27 अप्रैल को आयोजित होंगे। वहीं 4 गांव के बाजार चुनाव को देखते स्थगित कर दिए गए हैं। जनपद पंचायत चारामा के ग्राम पंचायत कोटत में 26 अप्रैलकी जगह अगले दिन शनिवार को साप्ताहिक बाजार लगेगा। जनपद पंचायत कांकेर अंतर्गत ग्राम पंचायत कोदागांव, बागोडार, बेवरती, मरकाटोला और सरंगपाल में 27 अप्रैल शनिवार को साप्ताहिक बाजार लगेगा। जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा अंतर्गत ग्राम पंचायत कोयलीबेड़ा, हरनगढ़ और नागलदण्ड में साप्ताहिक बाजार को स्थगित किया गया है। इसी तरह जनपद पंचायत अंतागढ़ के ग्राम पंचायत अर्रा में लगने वाला साप्ताहिक बाजार को भी स्थगित किया गया है।

ढिल्लन को 2 व त्रिपाठी को 9 मई तक रिमांड

रायपुर। शराब कारोबारी त्रिलोक सिंह (पप्पू) ढिल्लन को कोर्ट ने 2 मई तक रिमांड पर एसीबी को सौंप दिया है। पप्पू को एसीबी ने कल ही कोच्चि से हिरासत में लेकर आज रायपुर पहुंची और कोर्ट में पेश किया। पिछले दिनों एसीबी ईओडब्लू की छापेमारी के दौरान वह घर पर नहीं मिला था। लेकिन लगातार पड़ताल के बाद उसकी गिरफ्तारी हो गई । इस बीच इसी घोटाले में बिहार से गिरफ्तार एपी त्रिपाठी को 6 दिनों की रिमांड आज खत्म होने के बाद पेश किया गया, कोर्ट ने उसे भी 9 मई तक तक रिमांड दे दिया है।

भाठागांव बस स्टैंड से दौड़ेगी 21 ई-बसें जल्द

रायपुर। परिवहन सचिव एस. प्रकाश और अपर परिवहन आयुक्त श्री डी. रविशंकर ने आज भाठागांव अंतर्राज्जीय बस स्टैंड का निरीक्षण किया। बस स्टैंड से 21 ई-बसों का संचालन किया जाएगा। जिसके लिए ढ़ाई एकड़ जमीन का चिंहाकन किया गया है। उक्त जमीन का परिवहन सचिव व अपर परिवहन आयुक्त ने अवलोकन किया और नगर निगम व विद्युत विभाग को मूलभूत अधोसंरचनाएं विकसित करने के निर्देश दिए। साथ ही परिवहन सचिव व अपर परिवहन आयुक्त ने पंडरी के ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर का निरीक्षण किया। पंडरी के ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर में लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया का अवलोकन किया। आम नागरिकों से लाइसेंस बनाने के प्रक्रिया के बारे में बातचीत की। प्रक्रिया पर संतुष्टि जाहिर की। उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस प्रशिक्षण कार्य को देखा। इसके साथ ही सिटी सेंटर के केंद्र का निरीक्षण कर लाइसेंस मुद्रण कार्य की जानकारी ली। अब ड्राइविंग लाइसेंस भी पासपोर्ट की तर्ज बनाया जाएगा। इसकी प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। सिंगल विंडो के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाएगा।

राजधानी में सेग्रिगेशन का फीडबैक लेने नागरिकों के पास पहुंचे कमिश्नर

रायपुर। रायपुर नगर निगम के कमिश्नर अबिनाश मिश्रा ने गुरुवार सुबह डब्ल्यूआरएस कॉलोनी में नागरिकों के घर - घर जाकर गीला और सूखा कचरा अलग -अलग लेने के कार्य का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने नागरिकों से फीडबैक भी लिया। नागरिकों से मतदाता पर्ची प्राप्त हुई कि नहीं इसकी भी जानकारी ली। निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तृप्ति पाणिग्रही ने बताया कि आज सुबह कमिश्नर श्री मिश्रा ने डब्ल्यूआरएस कॉलोनी में घर - घर जाकर सूखा और गीला कचरा अलग - अलग लेने के कार्य का निरीक्षण किया। इस बारे में उन्होंने नागरिकों से चर्चा भी की। साथ ही मतदाता पर्ची मिलने या नहीं मिलने की भी जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने बूढ़ापारा स्तिथ सेकेंडरी कचरा कलेक्शन पॉइंट का भी निरीक्षण किया यहां उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नागरिकों से कचरा कलेक्शन के बाद सेकेंडरी कलेक्शन पॉइंट से सूखा और गीला कचरा संकरी कलेक्शन पॉइंट में अलग - अलग पहुंचाने हेतु दो जेडएचओ नियुक्त करने के निर्देश दिए।

राजनांदगांव सीट पर चुनाव के लिए पुख्ता सुरक्षा तैयारी

■ सीएपीएफ, पैरामिलिट्री की 60 कंपनियां तैनात

राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल राजनांदगांव सीट पर शुक्रवार को वोटिंग होनी है। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। नक्सल क्षेत्र होने के कारण हाई सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं। सीएपीएफ, पैरामिलिट्री की 60 कंपनियों के अलावा मध्य प्रदेश की फोर्स भी तैनात की गई है।

राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में चार जिले हैं। कबीरधाम, खैरागढ़, राजनांदगांव और मोहला मानपुर है। मोहला मानपुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। इसके अलावा कवर्धा जिला भी आंशिक नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आता है। ऐसे में वोटिंग के दौरान इन दोनों क्षेत्रों में तैयारियां बढ़ा दी गई है। मोहला मानपुर में सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। राजनांदगांव के आईजीपी प्रभारी दीपक झा ने बताया- राजनांदगांव लोकसभा सीट पर चुनाव की तैयारी पूरी कर ली गई है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में हुए चुनाव के दौरान गढ़चिरौली और गोंदिया बॉर्डर और एमपी के सीमावर्ती जिलों में राजनांदगांव से फोर्स भेजी गई थी, लिहाजा राजनांदगांव में चुनाव के दौरान वहां से मदद मांगी गई है।

आईजीपी प्रभारी दीपक झा ने कहा नक्सल प्रभावित मोहला मानपुर के साथ ही बाकी के तीनों में जिलों में विशेष सतर्कता बरती गई है। एरिया डोमिनेशन किया जा रहा है, सोर्स को भी एक्टीवेट कर दिया गया है। ताकी कोई भी जानकारी मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। दीपक झा ने बताया कि राजनांदगांव में आचार संहिता लगने के

बाद 12 चैक पोस्ट बनाए गए। अब तक 4000 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है। मोहलामानपुर में सबसे ज्यादा शराब मिली है। भारी मात्रा में कैश भी जब्त किया गया है। कवर्धा में भारी मात्रा में गांजा जब्त किया गया, गुंडे बदमाशों पर भी कार्रवाई की गई।

राजनांदगांव सीट पर बीजेपी के संतोष पांडेय और कांग्रेस के भूपेश बघेल के बीच मुकाबला है। संतोष पांडेय सिटिंग एमपी है जबकि भूपेश बघेल पूर्व सीएम और दुर्ग की पाटन विधानसभा से विधायक हैं। राजनांदगांव लोकसभा सीट पर 1999 से बीजेपी का कब्जा है। इस सीट में राजनांदगांव, डोंगरगांव, डोंगरगढ़, खैरागढ़, खुज्जी, मोहला मानपुर, कवर्धा और पंडरिया विधानसभा आते हैं। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में कुल 2330 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

महासमुंद का महामुकाबला, मतदाता के साथ मतदानकर्मी भी उत्साहित

महासमुंद। महासमुंद लोकसभा सीट पर बीजेपी का लंबे समय से कब्जा रहा है। इस बार कांग्रेस ने इस सीट को जीतने के लिए पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू को मैदान में उतारा है।वहीं बीजेपी से रूपकुमारी चौधरी मैदान में हैं। 17 लाख से ज्यादा मतदाता दूसरे चरण के चुनाव में वोटिंग के लिए तैयार हैं। मतदान के लिए मतदानकर्मी भी पहुंच चुके हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

लोकसभा सीट में चुनाव के लिए मतदान दल पहुंच चुके हैं। मतदान दलों को चुनाव सामग्री का वितरण तीन जिलों में किया गया। इसके बाद मतदान दल चुनाव सामग्री का मिलान कर रुट चार्ट के मुताबिक वाहन में सवार होकर मतदान केंद्र के लिए रवाना हुए।

आप को बता दे कि महासमुंद लोकसभा मे तीन जिले महासमुंद , गरियाबंद , धमतरी आते हैं। इन तीन जिलों के आठ विधानसभा महासमुंद , खल्लारी, बसना, सरायपाली, राजिम, बिन्द्रानवागढ़ , धमतरी , कुरुद में 26 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी। महासमुंद लोकसभा के लिए 17 प्रत्याशी मैदान में हैं। जिसमें मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। कांग्रेस ने इस सीट से पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू को टिकट दिया है,जबकि बीजेपी की ओर से रुपकुमारी चौधरी मैदान में है।

महासमुंद लोकसभा में 17 लाख 62 हजार 477 मतदाता हैं। जिसमें पुरुष मतदाता 8 लाख 66 हजार 670 और महिला मतदाता 8 लाख 95 हजार 773 है।जबकि थर्ड जेंडर मतदाता 34 हैं।इन मतदाताओं के लिए 2147 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। जिनमें से 33 मतदान केन्द्र संवेदनशील हैं। बिन्द्रानवागढ़ के 09 मतदान केन्द्र अति संवेदनशील हैं। बिन्द्रानवागढ के 02 मतदान केन्द्रों के लिए 24 अप्रैल को ही हेलीकाप्टर से मतदान दल रवाना कर दिया गया था।

जिला निर्वाचन अधिकारी प्रभात मलिक ने कहा मतदान दलों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। मतदान दलों के लिए कृषि उपज मण्डी में पानी, कूलर की व्यवस्था की गयी है।

कांकेर लोकसभा अंतर्गत बालोद में मतदान की तैयारी पूरी

बालोद। जिले में होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी है। मतदान दल चुनाव सामग्री लेकर बूथ पहुंच रहे हैं। गुरुवार को कलेक्टर ने मतदान दलों को गुलाब का फूल देकर रवाना किया। इस दौरान डिप्टी कलेक्टर तरुणा साहू और उप निर्वाचन अधिकारी चंद्रकांत कौशिक ने भी गुलाब भेंट कर महिला मतदानकर्मियों को मतदान के लिए शुभकामनाएं दी। बालोद जिले की तीन विधानसभा संजारी बालोद, डौंडीलोहार और गुंडरदेही में कुल 814 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 10 संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिसमें महिला मतदानकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। तीन विधानसभा में 1-1 दिव्यांग मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां हर सुविधा मिलेगी। तीनों विधानसभा में 5-5 युवा मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

कांकेर लोकसभा अंतर्गत बालोद जिले के तीनों विधानसभा के 689000 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। 26 अप्रैल सुबह सात बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। फोर्स की कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है।वहीं संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इस दौरान मतदान दलों में भी काफी उत्साह नजर आया। एक तरफ मतदानकर्मी अपने जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर उत्साहित है तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी मतदानकर्मी हैं जिन्हें चुनाव कार्य में लापरवाही के लिए निलंबित किया गया है। बालोद में प जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रकांत कौशिक ने चार कर्मचारियों को निलंबित किया है। निलंबित कर्मचारियों में ग्राम पीपरछेड़ी के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 देवनारायण राणा, डौंडीलोहारा तहसीलदार कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड- 2 मिलापसिंह रावटे, तहसीलदार कार्यालय डौंडीलोहारा में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 वीरेंद्र कुमार उइके, और ग्राम नारागांव के हाईस्कूल में पदस्थ भृत्य पुष्पेंद्र सोनकर है।

भूपेश को वोट देना यानी नवाज खान, अकबर और ढेबर को वोट देना: विजय शर्मा

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले प्रदेश की सियासत गर्म है। हालांकि चुनानी शोरगुल कल ही थम गया था पर आरोप-प्रत्यारोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पूर्व सीएम और राजनांदगांव से लोकसभा प्रत्याशी भूपेश बघेल को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सभी को पता है कि भूपेश बघेल के नवाज खान से बेहद करीबी रिश्ते रहे हैं। कई मामलों में नवाज खान के ऊपर मामले भी दर्ज हैं। पांच साल तक भूपेश बघेल ने सरकार ने नहीं चलाई । सरकार अकबर और ढेबर चलाते रहे। उनकी जो सरकरा चली सब जानतें हैं। तुष्टिकरण की राजनीति जो परवान चढ़ी.उसे भी सब जानते हैं। तुष्टिकरण की राजनीति के चलते केवल वोटबैंक की राजनीति की।

विजय शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि कवर्धा में भगवा का अपमान, बिरनपुर में मासूम भुनेश्वर साहू की बरबर्ता से हत्या इनकी सरकार किनके संरक्षण में हुई?

अकबर ढेबर सरकार चलाते रहे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भूपेश को वोट देना यानी छत्तीसगढ़ को लूटने वालों को वोट देना, भ्रष्टाचारियों को वोट देना, नवाज खान, अकबर, ढेबर और सौम्या चौरसिया को वोट देने के समान है। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव लोकसभा के कई लोगों की जमीन हड़पने के उनके ऊपर आरोप लगे हैं। कई लोगों पर अत्याचार और गुंडागर्दी करने के आरोप लगते रहे हैं, चर्चा का विषय रहा कि भूपेश बघेल का संरक्षण होने की वजह से उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसे ही भूपेश बघेल की उप सचिव रही सौम्या चौरसिया का भी नाम चर्चा में चल रहा है। भाजपा का कहना है कि 16 महीने से जेल में बंद सौम्या चौरसिया की भूपेश बघेल वकालत करते रहे हैं। जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं।

कवर्धा में रवानगी से पहले मतदान दल हुआ परेशान

■ भीषण गर्मी में पतले टेंट के नीचे हुआ सामग्री वितरण

कवर्धा। 25 अप्रैल को तालपुर गांव की कृषि उपज मंडी में सुबह 6 बजे से पीठासीन अधिकारी और मतदानकर्मियों को मतदान सामग्री वितरण कर मतदान केंद्र के लिए भेजा गया। इस दौरान कलेक्टर जनमेजय मोहबे ने मतदान दल वाहन को हरी झंडी दिखाकर कर रवाना किया।आपको बता दें कि राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के कबीरधाम जिले में दो विधानसभा हैं। कवर्धा विधानसभा और पंडरिया विधानसभा आते हैं। दोनों विधानसभाओं में कुल 804 मतदान केंद्र हैं। जिसमें 6 लाख 53 हजार 438 वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। जिले में महिला वोटर्स की संख्या पुरुष वोटर्स से ज्यादा है।

कवर्धा जिले में महिला मतदाताओं की संख्या 03 लाख 28 हजार 83 है। वहीं पुरुष मतदाता 03 लाख 25 हजार 353 हैं। जिले में 2 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। वहीं दिव्यांग मतदाता 6 हजार 520 है। इस बार 23 हजार 730 युवा मतदाता पहली बार मतदान करेंगे। वहीं 88

मतदाता ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 साल से ज्यादा है।कलेक्टर जनमेजय मोहबे ने बताया कि 26 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए 25 अप्रैल सुबह 6 बजे से मतदान दल को सामग्री वितरण करने की शुरुआत की गई।

जिला निर्वाचन अधिकारी जनमेजय मोहबे ने कहा कवर्धा जिले के 804 मतदान केंद्र में सुरक्षाकर्मी की ड्यूटी लगाई गई है। जिले के 56 एलडब्ल्यू मतदान केंद्र और 14 क्रिटिकल मतदान केंद्र में आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की गई है।गर्मी और धूप को देखते हुए मतदान दलों के लिए पेयजल और कूलर की भी व्यवस्था कराई गई है।ताकि किसी को कोई समस्या ना हो साथ ही मेडिकल की टीम और एम्बुलेंस भी मौजूद है। लेकिन कलेक्टर के इन दावों और हकीकत के बीच लंबी खाई देखने को मिली। कवर्धा में मतदान दलों को रवाना करने से पहले स्ट्रांग रूम में अव्यवस्था देखने को मिली। तालपुर गांव के कृषि उपज मंडी के स्ट्रांग रूम में भीषण गर्मी से बचने के लिए कोई उपाय नहीं किए गए थे। 40 डिग्री से ऊपर तापमान में मतदान कर्मियों के लिए पतला टेंट लगाया गया था।जिसके नीचे मतदान कर्मियों को बैठाया गया।हजारों मतदान कर्मियों के लिए गिनती के कूलर की व्यवस्था की गई थी।जिनमें से कई सारे कूलर बंद थे। महिला कर्मी अपने पास रखे कागज और दुपट्टे के सहारे गर्मी से राहत पाने की कोशिश कर रहे थे।

इस बार जिला निर्वाचन आयोग ने मतदान दलों के लिए होने वाले भोजन व्यवस्था को खत्म कर दिया है, ट्रेनिंग के दौरान ही मतदानकर्मियों को स्पष्ट कर दिया है कि मतदान दलों को मिलने वाले पंचायत स्तर से भोजन की व्यवस्था नहीं होगी। मतदान दल को स्वयं ही राशन सामग्री अपने साथ लेकर जाना होगा।इसके बाद स्कूल के रसोईयों से भोजन बनवाना होगा।

कवर्धा में भूपेश बघेल के काफिले को पुलिस ने रोका

■ पूर्व मुख्यमंत्री की गाड़ी की ली गई तलाशी

कवर्धा। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस और एफएसटी की टीम लगातार सरहदी इलाकों में वाहनों की चेकिंग कर रही है। इस दौरान किसी भी वाहन में अगर प्रतिबंधित सामान मिलता है, तो उसे पुलिस जब्त कर ले रही है। साथ ही वाहन चालक और वाहन के मालिक पर कार्रवाई भी की जा रही है। इस बीच बुधवार को भूपेश बघेल के वाहन को रोक कर पुलिस की टीम ने चेकिंग की। हालांकि पूर्व सीएम के वाहन से कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद पुलिस टीम ने भूपेश बघेल के वाहन को जाने दिया।

दरअसल, छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल शुक्रवार को है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पुलिस और एफएसटी की टीम लगातार जिले में आने-जाने वाली सभी

वाहनों की जांच कर रही है। बुधवार को एफएसटी और कूकदूर पुलिस की टीम ने पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के कामठी में चुनाव प्रचार कर लौट रहै कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल के काफिले को रोका। इसके बाद टीम ने वाहन की चेकिंग की। हालांकि वाहन से कुछ भी सामान नहीं मिला। इसके बाद भूपेश बघेल के वाहन को आगे जाने दिया गया।

लोकसभा चुनाव को देखते हुए कबीरधाम जिले के सभी सरहदी सिमाओं पर पुलिस बैरिकेडिंग लगातार आने जाने वाले सभी वाहनों को बारीकी से चेकिंग कर रही है। बाहरी लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। वहीं, जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस लागातार सर्चिंग कर रही है। साथ ही सभी पोलिंग बूथों पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

बता दें कि छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में 26 अप्रैल को मतदान होना है। इस क्षेत्र में कुल 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। हालांकि यहां कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल और बीजेपी प्रत्याशी संतोष पाण्डेय के बीच मुकाबला है।

अनवर ढेबर ने हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका, सीआईबी को नोटिस जारी

बिलासपुर। शराब घोटाला मामले में एसीबी में दर्ज एफआईआर और गिरफ्तारी के खिलाफ कारोबारी अनवर ढेबर ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। जहां चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है।

प्रदेश में कथित शराब घोटाले को लेकर पूर्व में ईडी की तरफ से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में ईडी ने कारोबारी अनवर ढेबर, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के एमडी रहे अरुणपति त्रिपाठी, नितेश पुरोहित और त्रिलोक सिंह ढिल्लन को आरोपी बताते हुए गिरफ्तार किया था। ढेबर को पूर्व में हाई कोर्ट

से मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मिल गई थी, बाद में एंटी करप्शन ब्यूरो ने इसी मामले में ईओडब्ल्यू में मामला दर्ज करवाया है। इस मामले में ढेबर को महाराष्ट्र जाने के दौरान गिरफ्तार किया गया था। उनकी तरफ से हाईकोर्ट में लगाई याचिका में कहा गया है, कि पूर्व में इस मामले में दर्ज ईसीआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था, इसलिए एफआईआर और गिरफ्तारी अवैध है।

साधराम हत्याकांड की एनआईए जांच के लिए साय सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव को भेजा पत्र

रायपुर। कबीरधाम जिले में हुए साधराम हत्याकांड की जांच एनआईए से कराने साय सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव को आग्रह पत्र भेजा है। बता दें कि साधराम यादव हत्याकांड से

आक्रोशित परिजनों ने सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात की थी। इस दौरान परिजनों की मांग पर सीएम साय ने एनआईए से जांच कराने का आश्वासन दिया था। सीएम साय ने 28 फरवरी को एनआईए से जांच कराने का एलान भी किया था।

21 जनवरी की सुबह कबीरधाम जिले के लालपुर कला में साधराम यादव का शव बरामद हुआ था। साधराम का गला रेतकर हत्या की गई थी। इस मामले की जांच के बाद पुलिस ने अयाज़ खान, इदरिस खान, सोफियान कुरैशी, अब्दुल मेहताब खान, शेख रफ़ीक और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान आरोपियों के मोबाइल से कश्मीर से जुड़े संदिग्ध नंबर बरामद हुए। पुलिस ने विवेचना में यह पाया कि आरोपियों की आवाजाही कश्मीर में भी थी। 20-21 अप्रैल की दरमियानी हुई हत्या के मामले में कबीरधाम पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल तथा अन्य अभिलेखों की जांच के बाद इस मामले की पृष्ठभूमि में कथित आतंकी और अतिवादी मुस्लिम संगठनों की संलिप्तता को देखते हुए इस मामले में 17 फ़रवरी को यूएपीए की धारा 16 जोड़ दी। इससे साफ हो गया था कि इस मामले की एनआईए जांच करेगी।

पिछड़ा वर्ग को साधने के चक्कर में सामान्य वर्ग को भूली पार्टियां

बिलासपुर। लोकसभा चुनाव को लेकर बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में जातिगत चुनावी महौल बन रहा है। दोनों ही पार्टी पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं को साधने और चुनाव अपने पक्ष में करने की कोशिश में लगे हैं। पार्टियों यह जानती हैं कि बिलासपुर में पिछड़ा वर्ग की आबादी अधिक है। इसे ध्यान में रखते हुए इसी वर्ग के उम्मीदवार का दोनों पार्टियों ने उतारा है। ताकि उनके प्रत्याशी की जीत पक्की हो जाए। लेकिन पिछड़ा वर्ग के चक्कर में कहीं ऐसा न हो कि अन्य समाज की उपेक्षा दोनों पार्टियों को भारी भी पड़ जाए।

बिलासपुर लोकसभा सीट में 20 लाख मतदाता है। राजनीतिक दलों ने अपने स्तर पर जातिगत आंकड़े तैयार किए हैं। जिसके अनुसार, लगभग 10 लाख 94 हजार मतदाताओं में 2 लाख 65 हजार आदिवासी, 2 लाख 25 हजार साहू समाज, 1 लाख 50 हजार यादव समाज, 1 लाख 35097 कर्मीचारी, 92 हजार मरार और पटेल, 75 हजार ब्राह्मण समाज, 15 हजार सूर्यवंशी और सतनामी, 5000 अन्य मतदाता है। इसके अलावा मुस्लिम समाज के मतदाता भी बड़ी संख्या में है। 2019 के चुनाव में 12 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया था, जबकि बाकी मतदाता वोट डालने मतदान केंद्र तक पहुंचे ही नहीं थे।

कांग्रेस और बीजेपी यह जानती है कि सबसे

ज्यादा संख्या में इन्हीं दो समाज के मतदाता हैं। बिलासपुर लोकसभा में सबसे ज्यादा संख्या वाली साहू समाज और दूसरे नंबर पर यादव समाज आता है। दोनों पार्टियां ओबीसी वर्ग को साधने के चक्कर में सामान्य और एससी-एसटी वर्ग को भूल गई है। देखा जाए तो 20 लाख की जनसंख्या में 10 लाख से भी ज्यादा की संख्या सामान्य और एसटी-एससी वर्ग की है। कहीं उनकी अनदेखी दोनों पार्टियों के लिए गेम खराब न कर दे।

राजनीतिक जानकार अखिल वर्मा ने कहा, दोनों ही पार्टियां अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत और 52 प्रतिशत आरक्षण देने की बात सदन में रखती रही हैं। लेकिन जब उनके प्रतिनिधित्व की बात आती है, तो चुप हो जाते हैं। ऐसे में दोनों ही पार्टी पिछड़ा वर्ग का फायदा उठाने की कोशिश में हैं। दोनों प्रमुख पार्टियों ने बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को प्रत्याशी बनाया है।

अखिल वर्मा ने कहा बिलासपुर के सामान्य और एससी-एसटी वर्ग के मतदाताओं की अनदेखी करना पार्टियों को नुकसान न पहुंचा दे। यदि पार्टियां पिछड़ा वर्ग के अलावा इन तीनों वर्ग को साधने में कामयाब हो जाए, तो निश्चित ही पार्टी की जीत होगी। लेकिन दोनों ही पार्टी इस समय पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं को लुभाने में लगी हुई है।

बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस और बीजेपी ने पिछड़ा वर्ग का उम्मीदवार उतारा है। इसके पीछे पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं को साधना दोनों दलों का टारगेट है। बिलासपुर जिले में 20 लाख मतदाताओं में लगभग 10 लाख 94 हजार मतदाता पिछड़ा वर्ग से आते हैं। बाकी के 10 लाख में सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मतदाता है। ऐसे में दोनों ही पार्टी ओबीसी उम्मीदवार उतार कर चुनाव जीतने जुगत लगा रही है। यहां साहू समाज के 2 लाख 25 हजार मतदाता हैं। वहीं यादव समाज के 1 लाख 70 हजार मतदाता हैं। इस दोनों वर्ग को जो भी पार्टी साध लेती है, उसकी सफलता के चांस ज्यादा बन सकती है। बिलासपुर का चुनाव जातिगत होने से यहां सभी की नजर बनी हुई है।

कांग्रेस में ही उठी संविधान के खिलाफ आवाज

उमेश चतुर्वेदी

मौजूदा चुनाव अभियान में कांग्रेस नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक आरोप हर जगह लगा रहा है। राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस का दावा है कि अगर मोदी सरकार को एक बार फिर बहुमत मिला तो वे संविधान को बदलकर रख देंगे। कांग्रेस चुनाव में संविधान पर संकट को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है। कांग्रेस देश को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है कि वह संविधान की रक्षा करेगी। लेकिन उसके ही एक नेता ने संविधान को लेकर गलत बयान दे दिया है। दक्षिण गोवा से कांग्रेस के उम्मीदवार विरियाटो फर्नांडिस ने एक चुनावी सभा में कह दिया कि गोवा पर भारतीय संविधान थोपा गया। जबकि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि गोवा के लोग अपने भाग्य का फैसला खुद करेंगे। विरियाटो का यह बयान एक तरह से अलगाववाद को बढ़ावा देता नजर आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल करते वक्त हर व्यक्ति भारतीय संविधान के प्रति शपथ लेता है। लेकिन विरियाटो यह शपथ भी भूल गए। विरियाटो यह भी भूल गए हैं कि संविधान को लेकर उनके नेतृत्व का रूख क्या है? कांग्रेसी नेतृत्व बीजेपी से संविधान को खतरे का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा है। विरियाटो तो इससे भी आगे निकल गए हैं। वे एक तरह से गोवा में अलगाववाद को ही बढ़ावा दे रहे हैं। विरियाटो के बयान का संदेश साफ है। अगर उनकी बात स्वीकार कर ली जाए या गोवा का युवा इस तथ्य को मान ही ले तो इसका मतलब है कि गोवा के लोगों को भारत से अपने रिश्ते पर विचार करना चाहिए। भारत की एकता और अखंडता को चुनौती देने वाले कांग्रेसी उम्मीदवार के इस बयान का गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने तीखा जवाब दिया है। सावंत ने इस बयान को भयावह करार दिया है। सावंत ने इस बयान पर हैरत जताते हुए कहा है कि वे इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान से स्तब्ध हैं। कांग्रेस की कथनी और करनी में कितना अंतर है, विरियाटो के बयान को इस संदर्भ में केस स्टडी के रूप में देखा जाना चाहिए। विरियाटो से अब तक कांग्रेस नेतृत्व ने कोई सवाल-जवाब नहीं किया है। इससे इस विवाद को और हवा मिलना स्वाभाविक है। यह सर्वविदित है कि 15 अगस्त 1947 को देश को लंबी गुलामी से आजादी मिली। लेकिन यह भी सच है कि तब गोवा पुर्तगाल का उपनिवेश था। गोवा की आजादी की लड़ाई तो पिछली सदी के तीस के दशक में गोवा कांग्रेस की स्थापना के साथ ही शुरू हो गया था। जब देश की आजादी की पूर्व पीठिका तैयार हो रही थी, तब समाजवादी धुरंधर डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने 1946 में गोवा का दौरा किया था। वहां उन्होंने पाया कि पुर्तगाली शासन के अधीन गोवा की स्थिति अंग्रेजों के गुलाम हिंदुस्तान से भी बदतर है। इसके खिलाफ डॉ लोहिया ने वहां भाषण दिया और धरने पर बैठ गए थे, जिसमें उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद से मधु लिमये जैसे समाजवादी गोवा जाकर धरना देते रहे। गोवा मुक्ति संग्राम के सेनानी भी संघर्षरत रहे। तब भारत में भी गोवा की आजादी को लेकर सवाल उठे। एक बार संसद में एक चर्चा के दौरान पंडित नेहरू ने गोवा के सवाल पर ऐसा जवाब दिया था, जिससे देश सन्न रह गया था। तब पंडित नेहरू ने कहा था कि भारत के खूबसूरत चेहरे पर गोवा एक मस्सा जैसा है, जिसे उंगलियों से भी थामा जा सकता है। विरियाटो के बयान से लगता है कि उन्हें या तो गोवा के इस इतिहास का पता नहीं है या फिर उसे जानने में उनकी दिलचस्पी नहीं है। तो क्या यह मान लिया जाए कि गोवा के मुक्ति संग्राम में देशभर से आए सेनानियों का संघर्ष बेकार गया? यह सच है कि गोवा मुक्ति संग्राम में शामिल स्वतंत्रता सेनानी तो यही मानते थे कि गोवा भी वैसे ही भारत का अभिन्न अंग है, जिस तरह यूपी है, बिहार है या महाराष्ट्र है। इसलिए उन्होंने उसकी मुक्ति का संघर्ष किया। दिलचस्प यह है कि अपने चुनावी भाषण में विरियाटो फर्नांडिस ने यह भी दावा किया है कि साल 2019 के चुनाव के दौरान उन्होंने अपना यह विचार तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के सामने भी व्यक्त किया था। ऐसा कहकर उन्होंने एक तरह से राहुल गांधी की सोच को भी कठघरे में खड़ा कर दिया गया है। भारत में एक विचारधारा ऐसी भी है, जो जम्मू-कश्मीर के विलय पर भी सवाल उठाते हुए उसकी स्वतंत्रता तक का पक्षधर रही है।

राहुल के सलाहकारों ने दूर कर दी मोदी की चिंता

अजय सेतिया

चुनाव प्रचार पूरे शबाब पर आ गया है, पहले चरण की वोटिंग के बाद यह धारणा बननी शुरू हो गई थी कि दक्षिण में भाजपा का मामला कुछ बन नहीं रहा और हिंदी बेल्ट में कमजोर पड़ रही है। इस धारणा के दो कारण सामने आए हैं, पहला कारण यह कि 2014 और 2019 में भाजपा हिन्दुओं के वोटों को एकजुट करने में कामयाब हो गई थी, लेकिन इस बार राहुल गांधी के जाति आधारित जनगणना के एजेंडे ने हिन्दुओं में फिर से फूट डाल दी है। पहले चरण की वोटिंग से यह संकेत निकला कि हिंदी बेल्ट में 2014 से पहले की तरह जाति आधारित वोटिंग हो रही है। कांग्रेस दलितों, आदिवासियों और ओबीसी के दिमाग में यह डालने में कामयाब होती दिखाई दी कि वह जाति आधारित जनगणना करवा कर उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण देगी, जो अब तक नहीं हुआ है।

आम धारणा है कि देश में आधी से ज्यादा आबादी ओबीसी की है, दलित और आदिवासी उनके अलावा है। कांग्रेस जाति आधारित जनगणना करवा कर उसके आंकड़े सुप्रीमकोर्ट में रखने का वादा कर रही है, ताकि सुप्रीमकोर्ट में लगी 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को बढ़वाया जा सके। दूसरा कारण वोट प्रतिशत का गिरना है, पिछले दो चुनावों में वोट प्रतिशत बढ़ रहा था, तो भाजपा की सीटें भी बढ़ रही थीं। हालांकि यह कोई पक्का आधार नहीं है कि वोट प्रतिशत गिरने से भाजपा की सीटें घटेंगी ही, लेकिन पिछले ट्रेंड को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी खुद आशंकित हो गए हैं। हिन्दी बेल्ट में भाजपा का ग्राफ सिर्फ राजस्थान में गिरने के संकेत नहीं है, जहां पहले चरण की 12 सीटों में से चार-पांच सीटों पर खतरा है। बल्कि हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड और बिहार में भी कांग्रेस के कुछ सीटें जीतने के आकलन आ रहे हैं। जैसे उत्तराखंड की पौड़ी और हरिद्वार, हिमाचल प्रदेश की मंडी और शिमला, हरियाणा की रोहतक, सिरसा, हिसार और कुरुक्षेत्र सीटें टक्कर वाली मानी जा रही हैं।

राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड में पिछली बार भाजपा सभी 44 सीटें जीती थीं। बिहार और महाराष्ट्र से भी भाजपा के लिए कोई उत्साहवर्धक रिपोर्ट नहीं आ रही। इन दोनों राज्यों की 88 सीटों में से 81 सीटें एनडीए जीता था। अब इन दोनों राज्यों में भी एनडीए की 10-12 सीटें घटने के आसार बन रहे हैं। इसलिए 370 और 400 पार वाला सपना छोड़कर भाजपा 303 और 353 बचाने की लड़ाई लड़ रही है। लेकिन कांग्रेस जो गलती हमेशा करती रही है, उसने उसी को फिर दोहरा दिया है। उसने अपने चुनाव घोषणा पत्र में मोदी को ऐसे दो मुद्दे दे दिए, जो मोदी के लिए रामबाण साबित हो रहे हैं। पहला मुद्दा है मुसलमानों को नौकरियों में आरक्षण देना, और दूसरा मुद्दा है अमीरों और मध्यम वर्ग की संपत्ति छीन कर गरीबों में बांटना। जिसे उन्होंने सम्पत्ति का पुनर्वितरण या वेल्थ रि-डिस्ट्रीब्यूशन कहा है। कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में पार्टी की नई सामाजिक और आर्थिक नीतियों का खुलासा किया है। कांग्रेस के चुनाव घोषणापत्र की ये दोनों ही नीतियां, न प्रेक्टिकल हैं, न संविधान सम्मत हैं, न भारतीय परंपराओं के अनुकूल हैं।

कांग्रेस ने अपने मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने के चक्कर में भाजपा को फिर से दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को अपने पक्ष में एकजुट करने में मदद की है। कांग्रेस ने मुसलमानों को शिक्षण संस्थाओं और नौकरियों में आरक्षण का वायदा करके भाजपा को मुद्दा थमा दिया है कि वह सत्ता में आई तो दलितों, आदिवासियों और ओबीसी के आरक्षण कोटे में से मुसलमानों को आरक्षण दे देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी बात को हाईलाईट कर रहे हैं। वह कर्नाटक का हवाला देते हैं कि कांग्रेस ने वहां ओबीसी का हक मार कर मुसलमानों को आरक्षण दे भी दिया है। कांग्रेस ने कर्नाटक में अपनी पिछली सरकार के समय भी मुसलमानों को चार प्रतिशत आरक्षण दिया था। जब भाजपा सत्ता में आई तो उसने मुसलमानों का आरक्षण बंद करके दलितों और ओबीसी को उनका हक वापस किया था, लेकिन दुबारा सत्ता में आते ही कांग्रेस ने मुसलमानों को शिक्षण संस्थाओं और नौकरियों में आरक्षण शुरू कर दिया है। अलबत्ता इस बार तो कांग्रेस पिछली बार से भी आगे निकल गई। उसने मुसलमानों की सभी जातियों को ओबीसी में शामिल कर दिया है। तथ्यों के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग भी मैदान में कूद गया है। उसने कुछ आंकड़े जारी किए हैं कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने मेडिकल कालेजों के पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में 150 मुस्लिमों को ओबीसी कोटे से एडमिशन दिलाया है। मुसलमानों की कुछ जातियां तो पहले से ओबीसी में आरक्षण पा रही हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग ने खुलासा किया है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने चुपके से सारी मुस्लिम जातियों को ही ओबीसी में शामिल कर लिया है।

नतीजा यह निकला कि मेडिकल कालेजों में ओबीसी कोटे की सारी सीटें मुसलमानों ने हथिया ली। मोदी और अमित शाह को बैठे ठाले मुद्दा मिल गया, वे अब इसी बात कर जोर दे रहे हैं कि कांग्रेस सारे देश में हिन्दू ओबीसी का हक मार कर मुसलमानों को देना चाहती है। भाजपा को इस नए मुद्दे से कितना लाभ होगा, यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कांग्रेस ने उसे दलित, आदिवासी, ओबीसी हिन्दुओं को भड़काने का एक मुद्दा तो थमा ही दिया है। कांग्रेस की नई आर्थिक नीति में सम्पत्ति का मूल्यांकन करके उसे देश के सभी नागरिकों में बांटने का कम्युनिस्ट सिद्धांत सोवियत संघ और चीन में पिट चुका है। लेकिन राहुल गांधी उसी पिटे हुए सिद्धांत का प्रचार करके कांग्रेस की जड़ों में मट्ठा डालने का काम कर रहे हैं। नरसिंह राव और मनमोहन सिंह ने बड़ी मुश्किल से नेहरू और इंदिरा गांधी की समाजवाद और कोटा परमिट वाली सोवियत अर्थव्यवस्था से देश को मुक्त किया था। आर्थिक उदारीकरण का युग आया, तो देश में निवेश के दरवाजे खुले, जिससे समृद्धि के दरवाजे खुले। अब राहुल गांधी उस कम्युनिस्ट व्यवस्था से भी खतरनाक नक्सली विचारधारा की वकालत कर रहे हैं, जिसमें लोगों की जीवन भर की कमाई सम्पत्ति उनसे छीन कर बाकी सब में बांटने की बाते कर रहे हैं। नक्सलवाद इसी सिद्धांत पर काम कर रहा है।

राहुल गांधी ने खुद 7 अप्रेल को अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस हमेशा बड़ा सोचती है, इसलिए जैसे उसने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जैसे राजाओं, महाराजाओं के प्रिवीपर्स बंद किए, वैसे ही लोगों की संपत्ति का बंटवारा करके क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। यही बात कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में भी लिख दी, लेकिन जब नरेंद्र मोदी ने उसे मनमोहन सिंह के 2006 के बयान के साथ जोड़ कर हिन्दुओं से उनकी संपत्ति छीन कर मुसलमानों में बांटने की बात कही, तो कांग्रेस बचाव मुद्रा में आ गई। वह सफाई दे रही है कि उसने ऐसा नहीं कहा, लेकिन राहुल गांधी के प्रमुख सलाहाकार और ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने यह कह कर कांग्रेस को संकट में डाल दिया कि किसी भी व्यक्ति के मरणोपरांत उसकी आधी संपत्ति पर सरकार का हक होना चाहिए, बाकी आधी सम्पत्ति पर उनके वारिसों का। क्या इसे देश में कोई स्वीकार करेगा कि उसकी जीवन भर की मेहनत से बनाई गई संपत्ति पर उसके बच्चों का हक न रहे। कोई भी व्यक्ति देश में उद्योग धंधे क्यों लगाएगा। कोई भी भारत में निवेश क्यों करेगा। सब उद्योगपति विदेशों में शिफ्ट हो जाएंगे, देश की सारी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। अब कांग्रेस को सैम पित्रोदा के बयान को उनकी निजी राय बताना पड रहा है। यह वही सैम पित्रोदा हैं, जिन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में हुए दंगों पर कहा था कि जो हुआ, तो हुआ। कांग्रेस भले ही उनके बयान का खंडन करे, लेकिन राहुल गांधी का भाषण, कांग्रेस का घोषणा पत्र और सैम पित्रोदा की थ्योरी बताती है कि कांग्रेस की नई सामाजिक और आर्थिक नीति क्या है।

सच्चाई यह है कि कांग्रेस की जमीनी जड़ें उखड़ चुकी हैं, किसी जमाने में कांग्रेस के अधिवेशनों और ग्रुप मीटिंगों में विचार विमर्श करके नीति तैयार होती थी। जिस जाति आधारित जनगणना का नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी ने विरोध किया, उसे राहुल गांधी बड़ा मुद्दा बना रहे है, कोई सैम पित्रोदा कांग्रेस की आर्थिक नीति बना कर दे रहा है। जिस पर पार्टी में किसी मंच पर चर्चा नहीं होती। राहुल गांधी और कांग्रेस ने सम्पत्ति के रि-डिस्ट्रीब्यूशन की जो थ्योरी रखी है, वह न तो व्यवहारिक है, न भारत का संविधान उसकी इजाजत देता है, न भारतीय परिवेश में संभव है। असंभव और आत्मघाती बातें करके राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को उस संकट से निकलने का रास्ता दे दिया, जो पहले चरण के मतदान के बाद दिखाई दे रहा था।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

योगकुण्डल्युपनिषद् (भाग-5)

गतांक से आगे...

इस क्रिया का निरन्तर अभ्यास करना चाहिए, सूर्यभेदन इसी क्रिया का नाम है। (उज्जायी प्राणायाम का का वर्णन) मुँह बंद रखते हुए दोनों नासा छिद्रों से वायु को धीरे-धीरे इस प्रकार खींचना चाहिए कि प्रवेश के साथ श्वास से ध्वनि होती रहे। इस प्रकार हृदय एवं कण्ठ तक वायु को भरे। पुन: पहले की तरह कुम्भक करके बायें नासा छिद्र से रेचन करना चाहिए, इसके करने से सिर की गर्मी, गले का कफ दूर हो जाता है, जठराग्नि बढ़ती है, नाड़ी जलोदर तथा धातुरोग भी समाप्त हो जाते हैं। उज्जायी नामक इस कुम्भक को स्थिर रहते अथवा चलते-फिरते कभी भी करते रहना चाहिए।

शीतली प्राणायाम में जिह्वा के द्वारा वायु को खींचकर पहले की तरह कुम्भक करके नासिका से वायु को धीरे-धीरे निकाले। इसके करने से प्लीहा, गुल्म, पित्त, ज्वर, तृषा आदि रोगों का शमन होता है।

भस्त्रिका प्राणायाम के लिए पद्मासन में बैठकर शरीर को गर्दन सहित सीधा करके सर्वप्रथम मुख को बन्द करके नासिका के द्वारा वायु को बाहर निकाले। पुन: इस तरह तीव्रता के साथ वायु को खींचे कि वायु का स्पर्श कण्ठ, तालु, सिर एवं हृदय को मालूम पड़े। फिर उसका रेचन करके पुन: पूरक करे, इस तरह बार-बार वेगपूर्वक लुहार की धौंकनी की तरह वायु को खींचे एवं निकाले। इस प्रकार शरीरस्थ वायु को सावधानी के साथ चलाना चाहिए। जब थकान मालूम पड़े, तब दाहिने (सूर्य) स्वर से वायु को खींचकर तर्जनी को छोड़कर नासिका को कसकर पकड़कर वायु का कुम्भक करे, फिर बायें नासा (इड़ा) छिद्र से निकाल देना चाहिए। इस प्रकार के अभ्यास से कण्ठ की जलन मिटती है एवं जठराग्नि की वृद्धि होती है। यह प्राणायाम सुख देने वाला, पुण्यकारी, पापनाशक तथा कुण्डलिनी को जगाने वाला है।

क्रमश: ...

विश्व बौद्धिक संपदा दिवस

कमलेश पांडे

विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि 9 अगस्त 1999 को, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) ने विश्व बौद्धिक संपदा दिवस को अपनाने का प्रस्ताव रखा। जबकि अक्टूबर 1999 में, डब्ल्यूआईपीओ की महासभा ने एक विशेष दिन को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में घोषित करने के विचार को मंजूरी दी, जो कि 26 अप्रैल है। तभी से विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाता है।

किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा सृजित कोई संगीत, साहित्यिक कृति, कला, खोज, प्रतीक, नाम, चित्र, डिजाइन, कापीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेन्ट आदि को बौद्धिक संपदा कहते हैं। क्योंकि जिस प्रकार कोई किसी भौतिक धन यानी फिजिकल प्रापर्टी का स्वामी होता है, उसी प्रकार कोई बौद्धिक सम्पदा का भी स्वामी हो सकता है। इसलिये बौद्धिक सम्पदा अधिकार प्रदान किये जाते हैं। आप अपने बौद्धिक सम्पदा के उपयोग का नियंत्रण कर सकते हैं और उसका उपयोग करके भौतिक सम्पदा यानी धन बना सकते हैं। इस प्रकार बौद्धिक सम्पदा के अधिकार के कारण उसकी सुरक्षा होती है और लोग खोज तथा नवाचार के लिये उत्साहित और उद्यत रहते हैं। बता दें कि बौद्धिक संपदा कानून के तहत, इस तरह के बौद्धिक सम्पदा के स्वामी को अमूर्त संपत्ति के कुछ विशेष अधिकार दिये गए हैं, जैसे कि संगीत, वाद्ययंत्र, साहित्य, कलात्मक काम, खोज और आविष्कार, शब्दों, वाक्यांशों, प्रतीकों और कोई डिजाइन आदि।

शब्द संपदा एवं शब्द संपत्ति एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, जिसका तात्पर्य बुद्धि संबंधित या बुद्धि संबंधित से अर्थात बुद्धि अथवा मस्तिष्क द्वारा पैदा की गई या उत्पादित की गई वस्तु, जिसे कोई व्यक्ति अपने बौद्धिक श्रम से उत्पादित करता है, वह उस व्यक्ति की बौद्धिक संपदा होती है। यदि साधारण बोलचाल की भाषा में समझाएं तो ऐसी वस्तु जिसे कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि से उत्पन्न करता है।

सामान्यत: संपदा व भौतिक वस्तुएं वे हैं जो विधि द्वारा मानव प्रवीणता एवं श्रम के अभ्यर्थिक उत्पाद के रूप में मान्यता प्राप्त करते हैं। उदाहरण- लेखकों की रचनाएं, अविष्कार कर्ताओं के आविष्कार, विचारकों के विचार, संकल्पना एवं साहित्य, संगीतात्मक, कलात्मक, नाट्य, ध्वनि, यांत्रिक, अभिव्यक्तियां।

बता दें कि इस आयोजन की स्थापना पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिजाइन दैनिक जीवन पर कैसे प्रभाव डालते हैं, के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी। वहीं, रचनात्मकता का जश्न मनाने के लिए और विकास के लिए रचनाकारों और नवप्रवर्तनकर्ताओं द्वारा किए गए योगदान का जश्न मनाने के लिए की गई। दरअसल, बौद्धिक संपदा संरक्षण के बारे में जागरूकता को और बढ़ावा देने के लिए, दुनिया भर में बौद्धिक संपदा संरक्षण के प्रभाव का विस्तार करने के लिए, विभिन्न सदस्य देशों से बौद्धिक संपदा संरक्षण कानूनों और विनियमों को प्रचारित करने और लोकप्रिय बनाने के लिए, आविष्कार-नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए और विभिन्न देशों में गतिविधियों और बौद्धिक संपदा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय विनिमय को मजबूत करना प्रमुख उद्देश्य है।

मालदीव की मुश्किल, नहीं होगा भारत की नीतियों में बदलाव

दीपक वोहरा

बीते 21 मई को मालदीव में संसदीय चुनाव हुआ, जिसमें इस्लामी राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू के गठबंधन पीपुल्स नेशनल कांग्रेस (पीएनसी) ने भारी जीत हासिल की, जिसने प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव (पीपीएम) के साथ गठबंधन किया था। आरोप हैं कि चीनी पैसे के बल पर नतीजे बदल दिए गए। मालदीव की संसद में कुल 93 सीटें हैं, जिनमें मतदाताओं की संख्या कहीं 1,000 से भी कम है, तो कहीं 3,000 से थोड़ा ज्यादा। निवर्तमान पीपुल्स मजलिस ने मुइज्जू की कई पहलों के साथ-साथ नामांकित कैबिनेट सदस्यों की नियुक्ति को भी रोक दिया था। अब कम से कम कुछ महीनों तक राष्ट्रपति समर्थक और विरोधी सांसदों को मारपीट करते हुए नहीं देखा जा सकता है। वर्ष 2023 में मुइज्जू इंडिया आउट अभियान चलाकर राष्ट्रपति का चुनाव जीते थे। यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया और उनके कुछ भारतीय पिछलग्गू इसे चीन की बहुत बड़ी जीत और भारत का भारी नुकसान बता रहे हैं, खासकर भारतीय सेना की छोटी-सी टुकड़ी के मालदीव छोड़ने के बाद। लेकिन ये विश्लेषक भ्रमित हैं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संबंध ऐसा खेल नहीं है, जिसमें एक पक्ष को जितना लाभ होता है, ठीक उतनी ही हानि दूसरे पक्ष को होती है। यह बार-बार साबित हो चुका है, लेकिन कुछ लोग इससे सीखना नहीं चाहते। श्रीलंका में बेहद भ्रष्ट गोटाबया राजपक्षे परिवार (जो चीन का वफादार सेवक था) का शासन 2022 के मध्य में ताश के पत्तों की तरह ढह गया। वह कोलंबो से भागकर मालदीव गए, लेकिन वहां से भी उन्हें जाने के लिए कहा गया, तो सिंगापुर गए। उन्हें चीनी आका ने छोड़ दिया। या म्यांमार का ही उदाहरण ले लीजिए। बीजिंग समर्थित सैन्य शासन लड़खड़ा रहा है, विपक्षी गठबंधन का देश के आधे से अधिक हिस्से पर नियंत्रण है। म्यांमार में दो शब्द सर्वाधिक घृणित हैं-चीन और सेना।

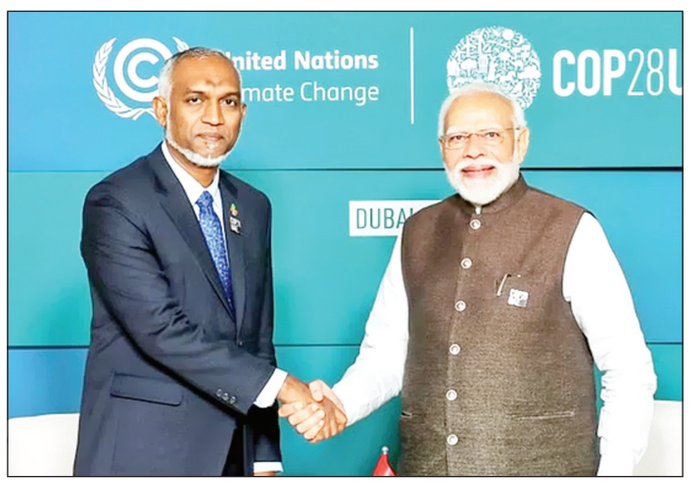

क्या मालदीव, जो 90,000 से ज्यादा वर्ग किलोमीटर में फैले 26 प्रवाल द्वीपों के आसपास करीब 1,200 मूंगा द्वीपों से बना है, अपने भविष्य पर ध्यान देगा? यदि ग्लोबल वार्मिंग मौजूदा गति से ही जारी रही, तो मालदीव अगले एक दशक में गायब हो जाएगा। फिर क्या वहां के लोग चीन जाएंगे?

मालदीव के आयात शुल्क संग्रह में भारी गिरावट आई है, क्योंकि उसका चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौता है। मार्च, 2024 में मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत को अपना करीबी सहयोगी बताते हुए ऋण राहत की गुहार लगाई, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई है और पर्यटकों की संख्या भी 30 फीसदी कम हो गई है। बड़ी संख्या में भारतीयों द्वारा मालदीव का दौरा रद्द करने से उसके पर्यटन उद्योग में भूचाल आ गया है और आतंकवादियों से भी उसके रिश्ते उजागर हो गए हैं। फिर भी अप्रैल 2024 में, भारत से आवश्यक खाद्य पदार्थों की मांग के बाद, जिनमें कुछ ऐसे सामान भी थे, जिनके निर्यात पर प्रतिबंध है, हमने वे चीजें भेजकर दयालुता दिखाई, जबकि चीन ने केवल पीने का पानी भेजा था। मालदीव के विदेश मंत्री ने ट्वीट किया कि वह भारत की उदारता के लिए दिल से आभारी हैं। भारत ने 1980 के दशक में तख्तापलट के प्रयास को विफल करने में मालदीव की सहायता की और 2000 के दशक में जब वहां पानी का घोर संकट था, तो पेयजल की आपूर्ति की थी। फेलिक्स श्वार्जेनबर्ग ने हमें 19वीं सदी के मध्य में बताया था कि अंतरराष्ट्रीय मामलों में कृतज्ञता जैसी कोई चीज नहीं होती है। यह बात हम जानते हैं।

वर्ष 2023 में आतंक समर्थक मुइज्जू ने अपने तीन कट्टर मुस्लिम मंत्रियों को हिंदू धर्म, भारत के प्रधानमंत्री और भारत के प्रति दुर्व्यवहार करने और अपने चीनी आका का पक्ष लेने के लिए कहा, क्योंकि वह चीन की यात्रा पर जा रहे थे। मुइज्जू अंतरराष्ट्रीय संस्थानों से धन चाहते हैं, लेकिन उन्होंने एक संदिग्ध चीनी कंपनी को निर्माण परियोजनाएं सौंपी हैं, जिसने कंबोडिया और अंगोला को धोखा दिया है और जो विश्व बैंक एवं एडीबी की काली सूची में है। मालदीव पर चीन का लगभग 1.3 अरब अमेरिकी डॉलर बकाया है, जो उसके विदेशी ऋण का पांचवां हिस्सा है। इस्लामी देशों में सबसे छोटा देश मालदीव पैगंबर से भी अधिक इस्लामी होने की कोशिश कर रहा है, और इस प्रक्रिया में खुद को नुकसान पहुंचाता दिख रहा है। चीन इस इस्लामी देश के साथ आ तो सकता है, लेकिन श्रीलंका की तरह जल्द ही पीछे हट जाएगा, क्योंकि मालदीव एक घातक कॉकटेल के नशे में है-कट्टरपंथी इस्लाम, भारी असमानता, सड़ी हुई राजनीति, ड्रग्स और आतंकवाद। खबरों के मुताबिक, मालदीव की संलिप्तता से भारत के खिलाफ 26/11 जैसे कम से कम दो हमले हुए, जिन्हें विफल कर दिया गया। हाशिये पर रहने वाले वर्गों के दस में से नौ मालदीव के युवाओं को दुनिया के इस्लामीकरण अभियान के लिए कट्टरपंथी बनाया गया है। वर्ष 2023 में भारतीय खुफिया विभाग ने एक मुस्लिम खनन इंजीनियर (जो विस्फोटकों के बारे में जानता था) को गिरफ्तार किया, जिसने अपने कुछ इंजीनियर दोस्तों के साथ मिलकर कई शहरों में विस्फोट किया था। उसकी हैंडलर मालदीव की एक महिला थी।

राष्ट्रपति बनते ही मुइज्जू तुर्किये के दौरे पर गए थे। अब यह बात उजागर हो गई है कि वह मालदीव के आईएस से जुड़े 36 युवाओं को सीरिया से माले लाने के लिए अंकारा से मदद मांगने गए थे। तुर्किये ने उनकी मदद की और बदले में तुर्किये निर्मित लाखों डॉलर के ड्रोन बेचे, जो मालदीव के समुद्री क्षेत्र में गश्त लगाते हैं। पहले यह काम भारत और मालदीव मिलकर करते थे। चीन से उन्होंने गुहार लगाई कि वह तालिबान को 2019 में अफगानिस्तान में गिरफ्तार किए गए 243 आईएस खुरासान-प्रशिक्षित मालदीव के लोगों को रिहा करने के लिए राजी करें, जिन्हें 21 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। लेकिन काबुल ने साफ इन्कार कर दिया। गरीबी, खतरनाक राजनीति, सनकी नेता, अवसरों की कमी और आतंकी धन ने मालदीव को सनकियों का मुल्क बना दिया है। वहां के पांच फीसदी सबसे समृद्ध लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 95 फीसदी हिस्सा है। हाल में मालदीव में धार्मिक असहिष्णुता, इस्लामीकरण और आतंकवाद में बढ़ोतरी हुई है। मालदीव डूबने के कगार पर है, पर दुनिया के पास इसके लिए समय नहीं है। इसलिए मौजूदा चुनावी नतीजे का हमारे द्विपक्षीय रिश्ते पर असर नहीं पड़ेगा। हम उसी तरह मालदीव से निपटेंगे, जैसे निपटना चाहिए।

आज का इतिहास

1964 तंजानिका और ज़ांज़ीबार विलय के साथ तंजानिया में जूलियस नायरेरे के साथ इसके पहले अध्यक्ष बने।
1966 7.5 तीव्रता वाले भूकंप से उज्बेकिस्तान का ताशकंद शहर पूरी तरह तहस नहस हो गया।
1970 विश्व बौद्धिक संपदा संगठन अस्तित्व में आया जब इसका चार्टर लागू हुआ।
1986 चेरनोबिल, यूक्रेनीएसएसआर के पास चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र को एक भाप विस्फोट का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप आग लगी, एक न्यूक्लियोमेडटाउन और 336,000 से अधिक लोगों का निकासी और पुनर्वास यूरोप में हुआ।
1989 ज़ेड इब्न शेखर जद अल-रिफाई की जॉर्डन के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए।
1989 तियानमेन स्क्वायर में अशांति फैलाने की निंदा करते हुए पीपुल्स डेली में एक संपादकीय प्रकाशित किया गया था, जो विरोध के बाकी हिस्सों को रोक देगा।
1989 बांग्लादेश के मानिकगंज जिले में एक तूफान आया, जिसमें 1,300 लोग मारे गए, जो इतिहास का सबसे घातक तूफान था।
1990 चीन में 6.9 तीव्रता वाले भूकंप से 126 लोग मारे गये।
1994 जापान के नगोया में ताइवान एयरबस ए-300 दुर्घटनाग्रस्त होने से 262 लोगों की मौत हो गयी।
1994 नागोया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने से ठीक पहले, चाइना एयरलाइंस फ्लाइट 140 के सह-पायलट ने अनजाने में गलतबटन को धक्का दे दिया, जिससे विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और जहाज पर सवार 271 में से 264 लोग मारे गए।
1995 लंबी हड़ताल के बाद बेसबॉल सीज़न शुरू किया गया था।
1996 वार्विकशायर के लिए शॉन पोलक ने 4 गेंदों में 4 विकेट लिए थे।
1996 जैकी ओ स्टफ की 4 दिनों की लंबी कार्रवाई .34.5 मिलियन पर समाप्त हुई थी।
1999 नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी का निधन।
2002 निष्कासित छात्र रॉबर्ट स्टाइनहूसर ने जर्मनी के एरफर्ट में गुटेनबर्ग-जिमनैजियम एरफर्ट में आत्महत्या करने से पहले 16 लोगों की हत्या कर दी और सात अन्य को घायल कर दिया।
2005 लेबनान से सैनिकों को अपने 29 साल के सैन्य कब्जे को समाप्त कर लिया गया था।

मोदी ने बदल दी चुनाव में भाजपा की रणनीति

अजय सेतिया

अठारहवीं लोकसभा के चुनाव शुरू हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह अपनी पार्टी भाजपा के लिए धुंआधार रैलियाँ और रोड शो कर रहे हैं। इन दोनों नेताओं ने चुनावों की घोषणा से एक महीना पहले ही लगभग सारे देश का एक एक बार भ्रमण कर लिया था। दोनों नेता भाजपा सरकार की उपलब्धियां और कार्यक्रम गिनाने के साथ साथ विपक्ष पर कड़े हमले भी कर रहे थे। इन दोनों के हमलों का मुख्य टारगेट राहुल गांधी थे। किसी अन्य नेता का नाम या जिक्र तो दोनों यदा कदा ही करते थे। ईडी-सीबीआई ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में डाल दिया, तो दोनों की पत्नियां विपक्ष की नुमाईशी नेता बन गईं। कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र आने के बाद नरेंद्र मोदी ने लीक से हटकर कांग्रेस पर पहला हमला तब किया, जब उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र लगता है। मोदी ने न कांग्रेस पर चोट की थी, न मुस्लिम लीग पर चोट की थी और न ही मुसलमानों पर चोट की थी। उन्होंने अपने कोर हिन्दू वोट बैंक को बताया था कि कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों के बारे में ही सोचती है, इसलिए हिन्दुओं को उससे सावधान रहने की जरूरत है।

अपने चुनाव घोषणापत्र को कांग्रेस ने न्याय पत्र का नाम दिया है। जिसमें पांच न्याय और 25 गारंटियों का जिक्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले बिहार के नवादा में, फिर उत्तरप्रदेश के सहारनपुर में और राजस्थान की पुष्कर रैली में कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र कहा। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र के आधे हिस्से में मुस्लिम लीग की छाप है, तो बाकी के आधे पर वामपंथियों का प्रभाव है। कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणापत्र में तीन ऐसे वादे किए थे, जो आज़ादी से पहले 1936 के मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र में भी थे, उन्हीं तीन मुद्दों के कारण भारत का विभाजन हुआ था। तब गांधी, नेहरू, पटेल की कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के वे तीनों मुद्दे ठुकरा दिए थे। पहला मुद्दा था- मुस्लिम पर्सनल लॉ की गारंटी, जबकि भारतीय जनता पार्टी इसके विपरीत मुस्लिम पर्सनल लॉ को खत्म करके यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा करती है। दूसरा, 1936 के मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र में कहा गया था कि वह बहुसंख्यकवाद के खिलाफ लड़ेगी। इसका मतलब था कि मुस्लिम लीग हिंदुत्ववाद के खिलाफ लड़ेगी। कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में कहा गया है कि भारत में बहुसंख्यकवाद के लिए कोई जगह नहीं। तीसरा, 1936 के मुस्लिम लीग के चुनाव घोषणा पत्र में कहा गया था कि मुसलमान छात्रों के लिए खास छात्रवृति और नौकरियों के लिए संघर्ष करेंगे। कांग्रेस के 2024 के चुनाव घोषणा पत्र में कहा गया है कि मुस्लिम छात्रों को विदेशों में पढ़ाई के लिए छात्रवृति की व्यवस्था की जाएगी और नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा।

हो सकता है कि यह एक संयोग हो, लेकिन इससे यह तो साबित हो गया कि कांग्रेस की रिसर्च टीम कितनी कमजोर है, और भाजपा की रिसर्च टीम कितनी तेजतर्रार है, जिसने कांग्रेस का घोषणापत्र आते ही मुस्लिम लीग का 88 साल पुराना चुनाव घोषणापत्र खोज निकाला। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा लेकर आगे बढ़ रहे थे, जिन्होंने कई बार दावा किया कि केंद्र सरकार की रसोई गैस उज्ज्वला योजना, हर घर शौचालय, और प्रधानमंत्री आवास योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ मुस्लिम महिलाओं को हुआ। इसके अलावा मुस्लिम महिलाओं का दिल जीतने के लिए उन्होंने तीन तलाक की प्रथा पर क़ानून बना कर रोक लगाई। उन्होंने युवा मुस्लिमों का दिल जीतने के लिए कई योजनाएं भी शुरू कीं, जैसे मुस्लिम छात्र छात्राओं को फ्री कोचिंग के लिए उड़ान योजना, ग्रेजुएशन करने वाली मुस्लिम लड़कियों को शादी के मौके पर केंद्र सरकार की ओर से 51000 रूपए की शगुन योजना, मुस्लिम कारीगरों को परंपरागत कला और हस्तकला की ट्रेनिंग योजना, हुनर हाट, मुस्लिम युवाओं के लिए सीखो और कमाओ योजना, 5 करोड़ मुस्लिम छात्र छात्रों के लिए प्रधानमंत्री छात्रवृति

योजना, हज पर जाने वाले मुसलमानों की संख्या बढ़ाना।

यानी मुसलमानों का दिल जीतने के लिए मोदी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन देश भर के दौरों में मिले फीडबैक से उन्हें विश्वास हो गया है कि मुस्लिम वोट एकतरफा कांग्रेस और इंडी एलायंस के घटक दलों के साथ जा रहा है, मुस्लिम वोट में सेंधमारी के उनके सारे प्रयास विफल हो गए हैं। इसलिए कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र को आधार बनाकर उन्होंने अपने कोर हिन्दू वोट बैंक को सुरक्षित करने के लिए अपने तेवरों को बदलना शुरू किया। कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र के तीन मुद्दों मुस्लिम पर्सनल लॉ की गारंटी, बहुसंख्यकवाद का खात्मा और नौकरियों में मुसलमानों को आरक्षण ने उन्हें अपने तेवर बदलने का मौक़ा दे दिया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में बहुसंख्यकवाद के खिलाफ जंग की घोषणा ने सांप्रदायिक और लक्षित हिंसा निवारण विधेयक की याद ताज़ा कर दी। यूपीए शासनकाल में सोनिया गांधी की राष्ट्रीय सलाहाकार परिषद ने इस विधेयक का प्रारूप तैयार किया था, जिसे मनमोहन सरकार संसद से पास करवा कर क़ानून बनाना चाहती थी।

यह बिल अगर क़ानून बन जाता तो मुसलमानों के हाथ में हिन्दुओं के खिलाफ बड़ा हथियार साबित होता। भाजपा, शिवसेना, अन्नाद्रमुक, तृणमूल कांग्रेस ने मिलकर बिल का विरोध किया, जिस कारण मनमोहन सरकार इसे पास नहीं करवा सकी। संभवत कांग्रेस घोषणापत्र में उसी बिल को पास करवाने का इशारा किया गया है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के घोषणापत्र को मुस्लिम लीग का चुनाव घोषणा पत्र कहा। कांग्रेस का घोषणापत्र भले ही मुस्लिम लीग का 1936 का चुनाव घोषणा पत्र देख कर न बनाया गया हो, कुछ हिस्सा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को देख कर जरुर बनाया गया है। 2005 में मनमोहन सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस राजिन्दर सच्चर की अध्यक्षता में सात सदस्यीय कमेटी बनाई थी, जिसे मुसलमानों की आर्थिक, सामाजिक स्थिति का अध्ययन करके उनकी हालत सुधारने के लिए सिफारिशें करने को कहा गया था। सच्चर कमेटी ने अपनी सिफारिशों में मुसलमानों को नौकरियों और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की थी। मुसलमानों को आरक्षण कांग्रेस और कम्युनिस्टों के एजेंडे पर हमेशा से रहा है। सच्चर कमेटी और बाद में कांग्रेस के नेता रहे पूर्व चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग की दूसरी सिफारिश हिन्दू धर्म छोड़कर मुस्लिम या ईसाई बने दलितों या आदिवासियों को भी आरक्षण देने की थी, जबकि भाजपा धर्मांतरण करने वालों को आरक्षण के लाभ से वंचित करने की समर्थक है। भाजपा का तर्क संविधान सभा में हुई बहस पर आधारित है, जहां संविधान सभा ने धर्म आधारित आरक्षण को ठुकरा दिया था। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, और अल्पसंख्यकों में से भी मुसलमानों का। नरेंद्र मोदी ने 19 अप्रेल को पहले चरण की वोटिंग के बाद इस मुद्दे को भी जोरदार ढंग से उठाकर हिन्दू दलितों और आदिवासियों को सतर्क किया कि कांग्रेस उनका हक मार कर मुसलमानों को देना चाहती है। अपने बयान के साथ उन्होंने 2006 का मनमोहन सिंह का वह बयान भी याद दिलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीखे तेवरों का कारण सिर्फ यह नहीं है कि पहले चरण की वोटिंग कम हुई है, बल्कि उनका फीडबैक यह है कि मुसलमानों ने पहले की तरह ही एकतरफा भाजपा के खिलाफ वोटिंग की है, जबकि हिन्दू रामजन्मभूमि मन्दिर निर्माण और 370 हटाए जाने के बावजूद उनकी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति से खफा हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी ने पहले चरण के चुनाव के दो दिन बाद 21 अप्रेल को राजस्थान के बांसवाड़ा में अपने हिन्दू वोट बैंक को संभालने के लिए मुस्लिम राजनीति के खिलाफ दूसरे चरण का हमला किया, जब उन्होंने कांग्रेस के चुनाव घोषणापत्र से सम्पत्ति के पुनर्वितरण वाले अंश को उठाया। मोदी ने पहले ही कहा था कि कांग्रेस के आधे चुनाव घोषणापत्र पर मुस्लिम लीग की छाप है, तो बाकी के आधे घोषणा पत्र पर वामपंथियों की छाप है।

जिस मुद्दे को उन्होंने बांसवाड़ा और बाद में टोंक - सवाई माधोपुर और छतीसगढ़ के जांजगीर में उठाया। जाति आधारित जनगणना के बाद सम्पत्ति के सर्वेक्षण और उसके बंटवारे वाले कम्युनिस्ट सिद्धांत को नरेंद्र मोदी ने हिन्दू महिलाओं के मंगलसूत्र से जोड़ कर और हिन्दुओं की सम्पत्ति ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले मुसलमानों में बांट दिए जाने का डर दिखा कर उन्होंने चुनाव को पूरी तरह हिन्दू-मुस्लिम बना दिया है। कांग्रेस भी पता नहीं किस दुनिया में है, किस क़ानून के तहत वह लोगों की अर्जित संपत्ति का पुनर्वितरण कर सकती है। कम्युनिस्ट विचारधारा की एक थ्योरी को कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में लिख दिया। नरेंद्र मोदी कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र के हवाले से हिन्दुओं को डरा रहे हैं कि द्रमुक और कम्युनिस्टों के समर्थन से कांग्रेस सरकार आ गई, तो न उनका सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा, न उनकी जीवन भर की मेहनत से जोड़ी गई संपत्ति सुरक्षित रहेगी। अब यह कांग्रेस को सोचना है कि उसके चुनाव घोषणा पत्र पर सोवियत संघ की पिट गई आर्थिक नीतियों का प्रभाव क्यों है, और उसके चुनाव घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग के विभाजनकारी एजेंडे की छाप क्यों है। लेकिन मोदी को विश्वास हो गया है कि वह विकास के एजेंडे पर नहीं जीत सकते, उन्हें अपने कोर हिन्दू वोट बैंक को ही बांधकर रखना होगा। इसलिए बीच चुनाव में उन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का चोला उतार फेंका, और 2014 वाले अपने मूल तेवरों में आ गए।

नीतियों की कई नावों पर पैर रखने से नुकसान

राजेश बादल

अपनी विदेश नीति से भटकाव का खामियाजा इन दिनों दुनिया के अधिकतर देश भुगत रहे हैं। आपसी संबंधों का आधार इंसानी रिश्तों के बुनियादी मूल्य और सिद्धांत नहीं रह गए हैं। वे अब आर्थिक धुरी के इर्द-गिर्द घूम रहे हैं। इसलिए विकसित विश्व के सभी राष्ट्रों को अपनी परंपरागत विदेश नीति छोड़नी पड़ रही है। वे तात्कालिक हितों के मद्देनजर रिश्तों की प्राथमिकताएं तय कर रहे हैं। परिणाम यह हुआ कि वे अपने बनाए जाल में ही उलझ गए हैं। कुछ मामलों के माध्यम से इसे समझना हो तो हिंदुस्तान के पास-पड़ोस से ही बेहतरीन नमूने पर्याप्त होंगे। ताजा उदाहरण पाकिस्तान का है। भारत से शत्रुतापूर्ण नजरिया उसकी सारी नीतियों का स्थाई भाव है। इसे केंद्र में रखते हुए वह जब शेष विश्व से संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है तो अपने ही जाल में और फंसता जाता है। ईरान, अमेरिका, चीन और रूस के साथ उसके संबंध इस श्रेणी में रखे जा सकते हैं। ईरान और पाकिस्तान बीते अनेक वर्षों से तनावपूर्ण रिश्तों के साथ जी रहे हैं। यहां तक कि वे एक-दूसरे की सीमा में जाकर मिसाइल जंग भी कर चुके हैं। ईरान कहता है कि बलूचिस्तान से सटे उसके इलाकों में पाकिस्तान हिंसा और आतंक को पनाह देता है। इसके उलट पाकिस्तान का भी कुछ ऐसा ही आरोप है। यह दोनों देशों के बीच स्थायी समस्या है और इसका व्यावहारिक हल फिलहाल तो नहीं दिखता। जब तक पाकिस्तान बलूचिस्तान नाम के देश को अपने से अलग नहीं हो जाने देता, तब तक समाधान का रास्ता नहीं मिलेगा, पर सवाल है कि पाकिस्तान ऐसा क्यों होने देगा? दोनों देशों के बीच स्थायी बैर भाव बनाए रखने वाला मुख्य कारण मजहबी है। पाकिस्तान अपने यहां शिया मुसलमानों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करता है और ईरान शिया बाहुल्य मुल्क है। सऊदी अरब से ईरान के रिश्ते अच्छे नहीं होने का यह बड़ा कारण है और सऊदी को पाकिस्तान से जोड़ने वाली वजह सुन्नी मुसलमान हैं। भारत और ईरान के बीच स्वाभाविक मैत्री की वजह यह भी है कि ईरान के बाद गैरमुस्लिम देशों में शियाओं की सर्वाधिक आबादी भारत में है। यह करीब सवा करोड़ है। अब दिलचस्प है कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी तीन दिन के लिए पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान ने उनका शानदार खैरमकदम किया। चंद रोज पहले इजराइल ने अपने हमले में ईरान का वायुसेना केंद्र और उसका एस-300 मिसाइल मारक तंत्र ध्वस्त करने का दावा किया था। ईरान ने इसका खंडन नहीं किया है। अब उसे मिसाइल तंत्र विकसित करने के लिए फौरन किसी सक्षम देश की मदद चाहिए। पड़ोसियों में केवल पाकिस्तान ही उसे यह सहायता दे सकता है. भारत और इजराइल के बेहतरीन रिश्तों के चलते भारत से उसे मदद नहीं मिल सकती थी और रूस-यूक्रेन युद्ध में उलझा है. वहां से भी कोई आशा ईरान नहीं कर सकता था. पाकिस्तान के इसमें दो स्वार्थ हैं। एक तो उसकी दिवालिया हो रही अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा और दूसरा ईरान से बलूचिस्तान के ग्वादर तक अरबों डॉलर की गैस पाइप लाइन का काम कम खर्च में पूरा हो जाएगा। पाकिस्तान के इस कदम से अमेरिका भन्नाया हुआ है।उसने ईरान पर बंदिशें लगा रखी हैं। गैस पाइपलाइन परियोजना पर वह पाकिस्तान को पहले ही गंभीर चेतावनी दे चुका है। अमेरिकी खुफिया विभाग ने जब पाकिस्तान और ईरान के बीच मिसाइल मित्रता के प्रति आगाह किया तो अमेरिका और आगबबूला हुआ। उसने पाकिस्तान और चीन को तगड़ा झटका दिया. बेलारूस की एक और चीन की तीन कंपनियों पर पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम को सहायता देने के आरोप में बंदिश लगा दी है। पहले भी वह पाकिस्तान की तेरह और चीन की तीन कंपनियों पर बंदिश लगा चुका है। उसे संदेह है कि पाकिस्तान ईरान को गुपचुप मिसाइल तकनीक और अन्य सहायता दे रहा है। अमेरिका ने अपनी ओर से एक तथ्य पत्र भी जारी किया है।

मंगलसूत्र चर्चा में, लेकिन महिलाएं चुनावी मैदान में क्यों नहीं

संदीप अग्रवाल

महिलाएं तो चुनावी मैदान में उस अनुपात में नहीं आयीं जितनी उनकी जनसंख्या में हिस्सेदारी है, या जितना आरक्षण देने का बिल भी पास हो चुका है, लेकिन उनका मंगलसूत्र जरूर राजनीतिक चर्चा में आ गया है। चुनावी आरोप प्रत्यारोप में मंगलसूत्र पर सबका ध्यान है, लेकिन मैदान में इस बार भी महिलाओं को उस संख्या में क्यों नहीं उतारा गया जितनी उम्मीद की जा रही थी? लोकतंत्र की मूल भावना यही है कि उसमें समाज के सभी वर्गों की हिस्सेदारी हो, विधायी सदनों में समुचित प्रतिनिधित्व हो। इसे सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारी रियायतें दी गई हैं, सुविधाएं दी गई हैं। लेकिन, अफसोस की बात है कि गणतंत्र के 75वें वर्ष में प्रवेश करने के बावजूद हम महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देने में नाकाम रहे हैं।

इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले आम चुनावों में वोट डालने वाले मतदाताओं में महिलाओं की हिस्सेदारी 48.2 प्रतिशत थी, और लोकसभा सांसदों में महिलाओं की संख्या मात्र 14.4 प्रतिशत। यही नहीं, कुल उम्मीदवारों में उनकी संख्या मात्र नौ फीसदी ही थी। इसका मतलब है कि हमारे राजनीतिक दल महिलाओं को टिकट देने में इच्छुक नहीं रहते। उनकी इस अनिच्छा को हम महिला आरक्षण बिल को लेकर उनके रवैये में भी देख सकते हैं, जिसे उसकी मंजिल तक पहुँचने में ढाई दशक से भी ज्यादा समय लग गया। दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश और सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए यह बेहद शोचनीय है कि यहाँ की करीब पचास फीसदी वयस्क आबादी को संसद और राज्य विधानसभाओं में पंद्रह फीसदी प्रतिनिधित्व भी हासिल नहीं है। प्रतिनिधित्व मिले भी तो कैसे, जब देश की सभी बड़ी पार्टियाँ उन पर भरोसा ही नहीं करतीं कि वे नेतृत्व कर सकती हैं। बेशक, सिद्धांतत: वे कितनी ही बड़ी बातें क्यों न करें, लेकिन व्यवहार के समय उनके आदर्शों पर राजनीति के तकाजे हावी हो जाते हैं।

सितंबर, 1996 में तत्कालीन प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा सरकार ने संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण के लिए

संसोधन बिल पेश किया था। सभी दलों ने इस विचार की सराहना भी की। लेकिन, इसके बाद हुए आम चुनावों में जब टिकट देने की बारी आई तो इनमें कोई दल ऐसा नहीं था, जिसने दस फीसदी महिला उम्मीदवारों को भी चुनाव मैदान में उतारा हो। 1996 से 2019 तक इस दौरान सात आम चुनाव हुए, कम से कम चार बार यह बिल सदन में पेश हुआ। लेकिन, राजनीतिक दलों ने अपनी सोच और तौर-तरीके बदलने में बहुत उत्साह नहीं दिखाया। पिछले लोकसभा चुनावों को देखें तो हालात में मामूली सा ही सुधार देखने में आया, जब सीपीएम, कॉन्ग्रेस, भाजपा, सीपीआई और बसपा जैसे दलों ने क्रमश: 14.8%, 12.8%, 12.6%, 8.2%, और 6.3% महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया था। जबकि इनमें कांग्रेस और बसपा तो ऐसी पार्टियाँ हैं, जिनका शीर्ष नेतृत्व महिला हाथों में रहा है।

चुनावों में महिला उम्मीदवारों को खड़ा करने में संकोच के पीछे उनकी जो भी मजबूरी रहती हो, लेकिन यह मानने वालों की कमी नहीं है कि पुरुषों के सामने महिला उम्मीदवार खड़ा करने से पार्टी की जीत की संभावनाएं कम हो जाती हैं। दुर्भाग्य से आम मतदाता की भी सोच यही है कि महिलाएं उनका प्रतिनिधित्व इतने अच्छे से नहीं कर सकतीं, जितना कि एक पुरुष सांसद या विधायक कर सकता है। जिस देश में लोग महिलाओं की वाहन चलाने तक की क्षमता को लेकर संदेह व्यक्त करते हैं, सरकार चलाने को लेकर उन पर भरोसा करने के लिए कैसे आसानी से मान सकते हैं। बावजूद इस सच्चाई के देश के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्रियों में से एक महिला प्रधानमंत्री थी और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, प.बंगाल, तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों की कमान महिला मुख्यमंत्रियों ने कई वर्षों तक सफलतापूर्वक संभाली है, देश की एक पूर्व और वर्तमान राष्ट्रपति महिला हैं। फिर भी लोगों को अपनी तंगनजरी पर इतना नाज है कि वे हवाई जहाज और अंतरिक्षयान उड़ाने वाली महिलाओं को नहीं देख पाते। हो सकता है कि राजनीतिक दलों द्वारा महिलाओं को तरजीह न दिए जाने के पीछे मतदाताओं का यह पूर्वाग्रह भी एक बड़ा कारण हो। इसीलिए महिलाओं के लिए चुनावों में आरक्षण बहुत जरूरी है ताकि पार्टियाँ उन्हें खड़ा करने के लिए बाध्य हों और मतदाता उन्हें उनका नेतृत्व कौशल दिखाने का अवसर देने के लिए।

केंद्र और राज्यों के चुनावों में महिलाओं के लिए आरक्षण अनिवार्य करने के लिए संशोधन विधयेक 1996, 1998, 1999 और 2008 में भी पेश किए जा चुके हैं। पहले तीन संबधित लोकसभा भंग होने के साथ निरस्त हो गए थे। 2008 में तो यह राज्यसभा में पेश हुआ और पारित भी, लेकिन लोकसभा भंग हो गई और यह भी इसी के साथ समाप्त हो गया। पिछले साल 19 सितंबर को इसी लक्ष्य को लेकर, 128वां संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया और 20 सितंबर को लोकसभा और 21 सितंबर को राज्यसभा में पास भी हो गया। लेकिन, वर्तमान चुनावों में इस पर अमल नहीं किया जा सका। दरअसल इसकी एक तकनीकी वजह है, वह यह कि इस विधेयक के लागू होने के बाद अब जो जनगणना होगी, उसके प्रकाशन के बाद ही यह व्यवस्था प्रभावी होगी क्योंकि महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए परिसीमन जनगणना के बाद किया जाएगा। राजनीति दलों और आम जन में इसे लेकर बहुत ज्यादा ऊहापोह भले ही रही हो, लेकिन स्थानीय निकायों में हम बीते तीन दशकों में इसके काफी सकारात्मक प्रभाव देख चुके हैं। 1993 में 73वां और 74वां संशोधन, जो पंचायतों और नगर पालिकाओं की सदस्यता में महिलाओं की 33% हिस्सेदारी सुनिश्चित करता है, पारित होने के बाद से अब तक, करीब तेरह लाख महिला उम्मीदवार इन निकायों में पहुँच चुकी हैं। महिलाओं के सशक्तीकरण के लिहाज से ही नहीं, बल्कि एक परिपक्व और विशाल लोकतंत्र की दृष्टि से भी यह हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसे संतोषजनक ही कहा जाएगा कि आजादी के बाद से अब तक संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है।

आम आदमी पार्टी का उत्थान और पतन

हरीश गुप्ता

यदि आप सोचते हैं कि मौजूदा लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान के दौरान राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी भाजपा का मुख्य निशाना हैं, तो आपकी धारणा शायद गलत है। इसमें कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री लगातार अपनी रैलियों में 'शहजादा' और गांधी परिवार के अन्य सदस्यों पर निशाना साधते रहे हैं।लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के किसी भी वरिष्ठ नेता को न तो जेल में डाला गया और न ही व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाया गया। वास्तव में, भाजपा नेता राहुल गांधी को एक ऐसी संपत्ति मानते हैं जो अपनी सहज टिप्पणियों या फिसलन भरी जुबान से मौका उपलब्ध कराते हैं।

अगर सत्ताधारी सरकार के करीबी सूत्रों की मानें तो असली निशाना आम आदमी पार्टी और उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं। कारण कई हैं, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि केजरीवाल को छोड़कर किसी भी राजनीतिक नेता ने दिल्ली विधानसभा चुनावों में भाजपा को एक बार नहीं बल्कि तीन बार हराने का गौरव हासिल नहीं किया है। यह इस तथ्य के बावजूद था कि पीएम मोदी ने 2015 और 2020 में केजरीवाल को हराने के लिए दिल्ली में अनेक रैलियों को संबोधित किया था।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि केजरीवाल ने भी अपनी क्षमता से ज्यादा पैर पसारने की कोशिश की थी जब उन्होंने 2014 के चुनावों में 432 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था और केवल पंजाब से चार सीट जीत पाए थे। 2019 में उन्होंने समझदारी दिखाई और 35 उम्मीदवार ही मैदान में उतारे। भगवंत सिंह मान लोकसभा में पंजाब का प्रतिनिधित्व करने वाले अकेले सांसद थे। इस चुनाव

में उन्होंने 22 उम्मीदवार उतारे हैं और दिल्ली, हरियाणा, गुजरात आदि में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है। इन 22 सीटों में से आप अकेले पंजाब में 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। फिर भी आप के भ्रष्टाचार विरोधी योद्धा अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं। यह मामला दुर्लभ है क्योंकि यह पहली बार है कि कोई मौजूदा मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव के बीच भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है। क्या इससे भाजपा को राजनीतिक तौर पर मदद मिलेगी और आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। इस अभूतपूर्व कार्य का परिणाम 4 जून को ही सामने आएगा।

आमतौर पर जिस रैली में प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि होते हैं वहां कोई भी पांच मिनट से ज्यादा नहीं बोलता। लेकिन नीतीश कुमार जोश से भरे हुए थे और 15 मिनट से अधिक समय तक बोले, यह एक दुर्लभ दृश्य था। जैसे कि यह पर्याप्त नहीं था, नीतीश कुमार ने अपना मानसिक संतुलन खोने के संकेत दिए और यह काफी शर्मनाक साबित हुआ। नीतीश ने यहां तक कह दिया कि एनडीए 4000 सीटें पार कर जाएगी। जैसे कि यह पर्याप्त नहीं था, नीतीश कुमार अपनी सीट पर वापस आए और मोदी के पैर छुए जिससे राजनीतिक तूफान आ गया।

यदि विपक्षी नेताओं ने इसे नीतीश द्वारा मोदी के सामने झुकने के रूप में चित्रित करने की कोशिश की, तो इससे सीएम के डिमेंशिया से पीड़ित होने की अफवाहों के बीच उनके स्वास्थ्य के बारे में चिंता भी बढ़ गई। नीतीश कुमार कई ऐसे काम करते रहे हैं जिससे पार्टी और कार्यकर्ताओं को भारी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। तब से, पीएम ने नीतीश कुमार के साथ किसी भी बैठक को संबोधित नहीं किया है, हालांकि मोदी गया और पूर्णिया में भी रैलियों को संबोधित करने गए थे।

मायावती के राजनीतिक ग्राफ में गिरावट

मायावती एक स्कूल टीचर थीं और पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांगने भाजपा नेता दिवंगत मदनलाल खुराना के पास गई थीं। वह असफल रहीं और सौभाग्य से, वह बसपा संस्थापक कांशीराम के संपर्क में आईं, जो एक दलित को भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। उन्होंने उन्हें तैयार किया और 1995 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने के बाद उन्हें यूपी का मुख्यमंत्री बनाया। उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सत्ता में बने रहने के लिए भाजपा, कांग्रेस या जिससे भी जरूरत पड़ी, उसके साथ गठबंधन किया। निर्णायक मोड़ तब आया जब वह 2007 में अपनी पार्टी के बल पर मुख्यमंत्री बनीं। 2009 में 6.17% वोटों के साथ 21 लोकसभा सीटें जीतकर बसपा एक अखिल भारतीय पार्टी बन गई। और फिर गिरावट शुरू हुई क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा को एक भी सीट नहीं मिली।

बलूचियों पर पाकिस्तानी हुकूमत के जुल्म

कुलदीप तलवार

पाकिस्तान में जहां एक तरफ लोग ईद मना रहे थे, वहीं बलूच समुदाय के लोग सड़कों पर पाकिस्तानी सरकार व सेना के अत्याचारों के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन कर रहे थे। उनका विरोध पाकिस्तान से आजादी पाने और लापता बलूचियों की तलाश की मांग को लेकर था। दरअसल इन लोगों को पाकिस्तानी सेना ने गायब करवाया था और आज तक पता नहीं चल सका है कि वे जिंदा हैं, या नहीं। मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन होने के कारण दुनिया भर में इसकी निंदा हो रही है। विभाजन के समय बलूचिस्तान पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के दबाव में उसे शामिल होना पड़ा। उस समय बलूच नेता कलात खान के संरक्षण में आजादी हासिल करने के लिए आंदोलन जारी था, जो बाद में और तेज हो गया। इसलिए बलूच राष्ट्रवादियों को पाकिस्तानी सरकार व सेना विद्रोही कहती है। उनकी नाराजगी पाकिस्तानी हुकूमत और सेना द्वारा ढाए जा रहे जुल्मों के कारण लगातार बढ़ती जा रही है। माना जा रहा है कि जब तक सेना और आईएसआई बलूचिस्तान पर अत्याचार बंद नहीं करती, उनमें पाकिस्तान से अलग होने की भावना खत्म नहीं होगी। अब तो उनकी आजादी की मांग अमेरिका और अन्य देशों तक पहुंच गई है। सरकार के अत्याचार से तंग आकर सैकड़ों बलूची पलायन करके विदेशों में बस गए हैं। वे रोज प्रदर्शन करके विश्व समुदाय का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर हस्तक्षेप करने की उम्मीद कर रहे हैं। इमरान खान की सरकार के समय से बलूचिस्तान के हालात और ज्यादा खराब हुए हैं। अब फौज के समर्थन से बनी गठबंधन सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। वह बलूचियों पर अत्याचार कर रही है। बलूचियों के लापता होने के पीछे खुफिया एजेंसी का हाथ बताया जा रहा है। जो लोग लापता बलूचियों की तलाश करने की मांग करते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है। लगभग 25,000 से अधिक बलूचियों का अपहरण हुआ है और उनमें से ढाई हजार से अधिक लोगों के गोलियों से छलनी व अत्याचारों के प्रमाण देने वाले शव बरामद हुए हैं। अब बाकियों की तलाश की मांग जारी है। ईद के अवसर पर हुए प्रदर्शन में सैकड़ों महिलाएं और बच्चे अपने लापता परिजनों की तस्वीरें लेकर शामिल हुए थे। मगर मौजूदा पाक सरकार व सेना उनकी कोई मदद नहीं कर रही है, बल्कि अब भी बलूचियों को जबरन गायब करने का सिलसिला जारी है। क्षेत्रफल के हिसाब से बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। यहां करीब एक करोड़ लोगों की आबादी है। प्राकृतिक संसाधनों के लिहाज से यह बाकी पाकिस्तान से ज्यादा समृद्ध है। पाकिस्तान के संविधान के अनुसार, बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों पर केंद्र और दूसरे प्रांतों का अधिकार कायम है, जबकि संसाधनों पर केवल बलूचियों को अधिकार मिलना चाहिए था। इस प्रांत में जो गैस पैदा की जाती है, उसकी आपूर्ति सारे पाकिस्तान में होती है और बलूचिस्तान को बहुत कम रॉयल्टी मिलती है। बलूची लोग चाहते हैं कि वहां से फ्रंटियर कोर की वापसी हो और उन पर लगाए गए मुकदमे वापस लिए जाएं। बलूचियों को इस बात का भी मलाल है कि ग्वादर बंदरगाह पर उन्हें काम देने के बजाय चीनियों को काम दे दिया गया है।

गर्मियों से राहत पाने के लिए बना लें कोकरनाग का प्लान

गर्मियों में घूमने के नाम पर दो ऑप्शन्स जो सबकी जुबान पर रहते हैं वो हैं उत्तराखंड और हिमाचल लेकिन इन दोनों से हटकर भी कई सारे ठिकाने हैं जहां जाकर आप गर्मियों से राहत पा सकते हैं। ऐसी ही एक जगह है कोकरनाग। जो बेहद खूबसूरत और शांत है। यहां तक कैसे पहुंचे और कौन सी जगहें हैं घूमने लायक जान लें इसके बारे में। हरी भरी वादियां और झरने इस जगह की खूबसूरती में लगाते हैं चार चांद

हिमाचल, उत्तराखंड के अलावा गर्मियों में घूमने वाली जगहों में आप जम्मू-कश्मीर को भी शामिल कर सकते हैं। यहां कई ऐसे ठिकाने हैं, जो आपकी छुट्टियों को यादगार बना देंगे। प्राकृतिक खूबसूरती से भरपूर कश्मीर में एडवेंचर के शौकीनों के लिए भी वैसे ऑप्शन्स की कमी नहीं। यहां का हर एक कोना खास है। जिसकी खूबसूरती में बस खो जाने का दिल करता है। अगर आप यहां के सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम को कवर कर चुके हैं या फिर इससे हटके किसी शांत जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो श्रीनगर के पास स्थित कोकरनाग का प्लान बनाएं।

कोकरनाग की खासियत

कोकरनाग जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित है। जहां जाकर आप अपने वीकेंड को बना सकते हैं मजेदार। कोकरनाग यहां की एक ऑफबीट जगह है, जिस वजह से यहां की खूबसूरती आज भी बरकरार है। यहां का शांतिपूर्ण और प्रदूषण रहित वातावरण इस जगह को और खास बनाता है। कोकरनाग आकर आप ताजे पानी के झरने, हरे-भरे बगीचे देखने के अलावा दूर-दूर तक फैले घास के मैदान में फोटोग्राफी के भी मजे ले सकते हैं।

कोकरनाग रोज़ गार्डन

कोकरनाग का रोज़ गार्डन यहां का बहुत ही मुख्य आकर्षण का केंद्र है, जिसे आपको देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। यहां रोजाना हजारों की संख्या में देश- विदेश से पर्यटक आते हैं। इस गार्डन में गुलाब की कई वैराइटी मौजूद हैं। जिनके साथ फोटोज़ क्लिक कराने के अलावा आपको उनके बारे में जानने का भी मौका मिलता है। इस गार्डन की देखरेख राज्य सरकार करती है। गार्डन में नहर और उसके ऊपर बना पुल इस जगह के आकर्षण को और बढ़ाने का काम करता है। श्रीनगर से मात्र 70 किमी. का सफर तय करके आप यहां पहुंच सकते हैं।

कोकरनाग झरना

कोकरनाग शहर से जुड़ी कई सारी पौराणिक कहानियां भी हैं। कोकरनाग झरना श्रीनगर से लगभग 80 किमी दूर है। झरने के आसपास हरियाली और रंग-बिरंगे फूल इस जगह की खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस झरने का पानी कई सारी समस्याओं के उपचार में भी फायदेमंद है।

कोकरनाग कब जाएं?

कोकरनाग घूमने का बेस्ट सीज़न गर्मियां ही हैं, क्योंकि इस दौरान आपको गर्म कपड़ों की जरूरत नहीं होती। वैसे जुलाई से सितंबर अंत तक भी प्लान कर सकते हैं।

कोकरनाग कैसे पहुंचें?

फ्लाइट से- अगर आप हवाई यात्रा करना चाहते हैं, तो आप श्रीनगर हवाई अड्डे के लिए सीधी फ्लाइट ले सकते हैं। एयरपोर्ट से कोकरनाग के लिए आपको टैक्सी मिल जाएगी। श्रीनगर और कोकरनाग के बीच की दूरी 90 किमी है

चिलचिलाती गर्मी में भी बेहद ठंडी रहती हैं ये जगह, कम ही लोग करते हैं यहां जाने की हिम्मत

चिलचिलाती गर्मी से हर किसी की हालत बुरी हो रही है। जैसे-जैसे गर्मी बढ़ती है, वैसे ही कई जिलों में रेड अलर्ट जारी हो जाता है। वहीं गर्मी से खुद को बचाने के लिए ज्यादातर लोग ठंडी जगहों पर जाने की प्लानिंग करने लगते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ ठंडी जगह ऐसी भी हैं, जहां मई-जून के महीने में भी जाना मुश्किल होता है। यहां जानिए भारत की सबसे ठंडी जगहों के बारे में।

कारगिल, जम्मू और कश्मीर

कारगिल शहर भारत के सबसे ठंडी जगहों में से एक है। यह सुरू नदी के किनारे है और 2,676 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कारगिल के सबसे करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ियों पर महलों के खंडहरों का एक ऐतिहासिक शहर है जिसे पश्कुम कहा जाता है। सर्दियों के दिनों में यहां का तापमान 48 डिग्री रहता है।

लेह लद्दाख

लद्दाख की राजधानी, लेह एक बहुत फेमस पर्यटन स्थल है। गर्मियों में घूमने के लिए ये एक बेहतरीन जगह है, जहां तापमान हमेशा कम ही रहता है। शांति स्तूप, लेह पैलेस, पैंगोंग झील और कई अन्य झीलें और मठ लेह में जरूर देखें।

नॉर्थ सिक्किम

नॉर्थ सिक्किम दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। इसे भी भारत की सबसे ठंडी जगहों में से एक माना जाता है। जीरो पॉइंट, युमथांग वैली, लाचुंग मठ, क्रोज झील देखने लायक है। गर्मी की छुट्टियों में यहां घूमने के लिए जा सकते हैं।

सेला दर्रा, तवांग

अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थित, सेलांग एक बेहद ठंडी जगह है, जो बौद्ध शहर तवांग को तेजपुर और गुवाहाटी से जोड़ता है। यह जगह पूरे साल बर्फ से ढकी रहती है, जो नेचर लवर्स के लिए अच्छी है।

भारत के इन बीचेज पर तैरने से पहले जरूर बरतें ये सावधानियां

जब भी वेकेशन टाइम होता है, तो लोग कहीं न कहीं घूमने का प्लान जरूर बना लेते हैं। ऐसे में कुछ लोगों को पहाड़ों पर तो कुछ लोगों को बीचेस पर वेकेशन मनाना पसंद होता है। वैसे बीचेस पर मस्ती करना लगभग हर किसी को पसंद होता है। आपको बता दें कि भारत में ऐसे कई डेस्टिनेशन हैं, जहां पर आप बीच पर घूमते हुए ढेर सारी मस्ती कर सकते हैं। हांलाकि आप हर बीच पर उतनी ही मस्ती कर सकें, यह जरूरी नहीं है।

दरअसल, भारत देश में ऐसे कई बीचेस हैं, जहां पर स्विमिंग आदि करना बेहद खतरनाक माना जाता है। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको भारत में मौजूद कुछ ऐसे बीचेस के बारे में बताने जा रहे हैं। जहां पर घूमना व स्विमिंग करना ज्यादा सेफ नहीं है। तो आइए जानते हैं भारत में मौजूद इन बीचेस के बारे में...

अरम्बोल बीच, गोवा

वहीं गोवा का अरम्बोल बीच काफी ज्यादा फेमस है। यहां पर अक्सर लोग अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ आते हैं। अरम्बोल बीच जितना ज्यादा खूबसूरत है, उतना ही ज्यादा खतरनाक भी है। यह बीच एक चट्टानी इलाके में है। हांलाकि अरब सागर की तेज लहरें स्विमिंग को मुश्किल बनाती हैं। इसके अलावा पानी के नीचे छिपी बड़ी चट्टानों की वजह से आपको स्विमिंग के दौरान अधिक सावधानी बरतने की जरूरत होती है।

मरीना बीच, चेन्नई

चेन्नई का प्लान बनाने वाले लोग मरीना बीच घूमने जरूर जाते हैं। बता दें कि मरीना बीच को दुनिया के सबसे लंबे समुद्र तटों में से एक माना जाता है। इसलिए अगर आप यहां पर स्विमिंग करना चाहते हैं, तो आपको इस बीच की गहराई में जाने को लेकर अतिरिक्त सावधान रहना चाहिए।

यारदा बीच, आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के पास याराडा बीच स्थित है। यह बीच हरी-भरी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस बीच की खूबसूरती को देखते हुए लोग यहां पर वक्त बिताना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन यहां की तेज लहरें इसको देश की सबसे खतरनाक बीचेस बनाती हैं। ऐसे में अगर आप भी यहां पर आते हैं, तो आपको यहां काफी सोच-समझकर स्विमिंग करनी चाहिए।

कोवलम बीच, केरल

कोवलम बीच केरल में बेहद पॉपुलर बीच है। अक्सर लोग अपने परिवार या दोस्तों के साथ यहां आना पसंद करते हैं। लेकिन यहां आने के दौरान थोड़ा अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत होती है। क्योंकि तेज लहरें होने की वजह से यहां पर डूबने की दुर्घटनाएं देखी गई हैं। इसलिए अगर आप इस बीच पर जाते हैं, तो वॉर्निंग साइंस को अनदेखा न करें। इसके साथ ही लाइफगार्ड इंस्ट्रक्शन को भी फॉलो करें।

डुमस बीच, गुजरात

गुजरात के डुमस बीच पर अक्सर लोग जाने से कतराते हैं। यह देश के सबसे रहस्यमयी समुद्र तटों में से एक माना जाता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह हॉन्टेड बीच है। इसलिए जब लोकल लोग इस बीच पर आते हैं, तो पानी में बहुत अंदर तक नहीं जाते हैं।

लोगों के मन में इस बीच को लेकर बनी धारणा इसको अनोखा और खतरनाक बनाती है।

सिक्किम की युमथांग वैली है गर्मियों में घूमने के लिए परफेक्ट

गर्मियां सिक्किम घूमने के लिए बेस्ट सीजन हैं। वैसे तो यहां कई सारी जगहें हैं जो देखने लायक हैं लेकिन एक जगह ऐसी है जिसे देखे बिना यहां की यात्रा मानो अधूरी है और वो है युमथांग वैली। जिसे फूलों की घाटी भी कहा जाता है। फरवरी से जून तक ये घाटी फूलों की चादर ओढ़ लेती है। जानेंगे आज इसी जगह के बारे में।

सिक्किम में एक बेहद खूबसूरत जगह है जहां जाकर आपको जन्नत में होने का एहसास होता है जिसका नाम है युमथांग वैली। सिक्किम की राजधानी गंगटोक से तकरीबन 140 किमी उत्तर में स्थित है युमथांग घाटी। जिसे फूलों की घाटी नाम से भी जाना जाता है। जहां आकर आप कई तरह के खूबसूरत फूलों का दीदार कर सकते हैं। अगर आप सिक्किम घूमने का प्लान कर रहे हैं, तो इस जगह को देखना बिल्कुल भी मिस न करें। 3,564 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह वैली एडवेंचर और नेचर लवर्स के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है।

क्यों खास है युमथांग वैली?

युमथांग वैली को खासतौर से अपने शानदार नजारे के लिए जाना जाता है। घाटी में रोडोडेंड्रोन फूलों (राज्य फूल) की 24 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जो फरवरी से जून तक खिलते हैं। इस घाटी में कई गर्म झरने भी मौजूद हैं, जो त्वचा से जुड़ी कई तरह की समस्याएं दूर करती हैं। इसके अलावा यहां आकर आप ट्रेकिंग और कैम्पिंग जैसी एक्टिविटीज भी एन्जॉय कर सकते हैं।

युमथांग वैली के लिए जरूरी टिप्स

किसी भी मौसम में युमथांग वैली का प्लान बनाएं, अपने साथ गर्म कपड़े जरूर कैरी करें, क्योंकि ये जगह काफी ऊंचाई पर स्थित है जिसकी वजह से यहां का मौसम बदलता रहता है।

युमथांग घाटी में एटीएम वगैरह की सुविधा नहीं है, तो अपने साथ कुछ कैश जरूर रखें।

डायरेक्ट युमथांग पहुंचने का प्लान थकान भरा हो सकता है इसलिए पहले गंगटोक से लाचुंग जाएं और वहां नाइट स्टे करें फिर अगली सुबह युमथांग के लिए निकलें।

युमथांग घाटी घूमने के लिए खास परमिट की जरूरत होती है, तो यहां जाने से पहले परमिट जरूर ले लें।

युमथांग वैली जाने का बेस्ट सीज़न

युमथांग घाटी घूमने का बेस्ट सीज़न फरवरी से लेकर जून तक रहता है, तो इसी के बीच प्लान बनाएं। सितंबर से दिसंबर तक ये जगह बर्फ से ढक जाती है।

कैसे पहुंचे युमथांग वैली?

युमथांग वैली गंगटोक से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सड़क मार्ग यहां तक पहुंचने का बेस्ट ऑप्शन है। युमथांग वैली तक पहुंचने के लिए गंगटोक से लाचुंग पहुंचें और फिर वहां से युमथांग। लाचुंग से, युमथांग पहुंचने में लगभग 50 मिनट का वक्त लगता है।

मध्यप्रदेश के इस शहर को मिला बटरफ्लाई पार्क, यहां आकर खुश हो जाएगा आपका मन

रंग-बिरंगे पक्षियों को देखकर भला किसका मन खुशी से नहीं झूम उठता होगा। शायद आप भी हजारों की संख्या में पक्षियों को देखकर खुश हो जाते होंगे। वहीं वर्तमान समय में तितलियों की प्रजातियां विलुप्त सी हो गई हैं। कई लोग तितलियों को देखना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। देश के कई अलग-अलग हिस्सों में तितली पार्क मौजूद हैं। जहां पर आप एक साथ दर्जनों की संख्या से भी अधिक तितलियां देख सकते हैं। ऐसे में अगर आपको भी तितलियां देखना व उनके बीच घूमना काफी अच्छा लगता है, तो यह आर्टिकल आपके लिए है। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको मध्यप्रदेश में स्थित बटरफ्लाई पार्क के बारे में बताने जा रहे हैं। साथ ही यह भी जानेंगे कि यह पार्क मध्यप्रदेश के किस शहर में स्थित है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में बटरफ्लाई पार्ट खोला गया है। एमपी का खंडवा शहर एक लोकप्रिय ट्रेवल डेस्टिनेशन के रूप में भी जाना जाता है। इस शहर की खूबसूरती को एक्सप्लोर करने के लिए यहां पर रोजाना हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। खंडवा में स्थित बटरफ्लाई पार्क काफी ज्यादा खास है। इस पार्क को 14 हेक्टेयर में तैयार किया जा रहा है। इस पार्क में तितलियों को देखने के साथ ही मौज-मस्ती कर सकते हैं। पार्क में फव्वारे का भी निर्माण किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक खंडवा में इंदिरा सागर बांध की झील के किनारे पर इस खूबसूरत पार्क का निर्माण प्राकृतिक सौंदर्य के बीच किया जा रहा है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

मोदी-राहुल के भाषणों पर चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिस

नई दिल्ली। आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपों पर चुनाव आयोग ने पीएम मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भाषणों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने 29 अप्रैल सुबह 11 बजे तक दोनों पार्टियों से जवाब मांगा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के नेताओं के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी और धर्म, जाति, संप्रदाय और भाषा के नाम पर लोगों के बीच नफरत फैलाने और अलगाववाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। चुनाव आयोग ने इस मामले में जन प्रतिनिधि कानून की धारा 77 की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए स्टार प्रचारकों के आचरण के लिए पार्टी अध्यक्षों को जिम्मेदार माना है और दोनों पार्टियों के अध्यक्षों को नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने 29 अप्रैल को सुबह 11 बजे तक नोटिस का जवाब देने का निर्देश दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को अपने उम्मीदवारों, स्टार प्रचारकों के आचरण की जिम्मेदारी लेनी होगी।

कन्नौज से चुनावी मैदान में उतरे अखिलेश, किया नामांकन

लखनऊ। शुक्रवार को होने वाले दूसरे चरण के मतदान से पहले, समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। सपा प्रमुख, (जिन्होंने 2000 और बाद में 2004 और 2009 में इस सीट का प्रतिनिधित्व किया था) ने राम गोपाल यादव सहित पार्टी नेताओं की उपस्थिति में नामांकन दाखिल किया। पत्रकारों से बातचीत में रामगोपाल यादव ने कहा कि सपा भारी अंतर से सीट जीतेगी। उन्होंने कहा, भाजपा उम्मीदवार इस सीट पर अपनी जमानत जब्त कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि मैंने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी, नेताओं, कार्यकर्ताओं और सभी की भावना थी कि मैं यहां से समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ूं। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मुझे उम्मीद है कि मुझे यहां से आशीर्वाद मिलेगा।

कन्नौज से प्रत्याशी बदलने पर जयंत का अखिलेश पर तंज

लखनऊ। समाजवादी पार्टी में बार-बार टिकट बदलने पर राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने तंज कसा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की कन्नौज से उम्मीदवारी पर रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि देखिए, इंतजार कीजिए। हो सकता है कि अगले दिन कोई और उम्मीदवार बन जाए। आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि सच तो ये है कि मैं उत्तर प्रदेश में विपक्ष को जीतते नहीं देख रहा हूं। ये (भारत गठबंधन) वाकई फ्लॉप हो रहा है। इनमें अंदरूनी कलह बहुत है, राज्यों में ये आपस में ही लड़ रहे हैं, इसलिए जब ये चुनाव से पहले लड़ रहे हैं तो चुनाव के बाद इनका अस्तित्व क्या होगा। उन्होंने बसपा प्रमुख मायावती के अलग पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य के लिए काम करेंगे वाले बयान पर कहा कि यह लंबे समय से चली आ रही मांग है। समय-समय पर यह मांग होती रही है कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन किया जाए।

सैम पित्रोदा के बयान पर भड़कीं मायावती

लखनऊ। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा की विरासत कर पर टिप्पणी ने राजनीतिक क्षेत्र में एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी और पार्टी के अन्य नेताओं द्वारा बहुचर्चित विवादास्पद बयान पर प्रतिक्रिया देने के बाद, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती भी कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसीं। एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता द्वारा विरासत कर का विचार और वकालत राजनीति से प्रेरित कदम है और इसका मतलब गरीबों का कल्याण नहीं है। मायावती ने एक्स पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा भारत में धन के वितरण की आड़ में, अमेरिका की तरह, निजी सम्पत्ति पर 'विरासत टैक्स' की सोच व उसकी पैरवी गरीबों की भलाई का कम व राजनीति से प्रेरित इनकी 'गरीबी हटाओ' की चर्चित विफलता पर से लोगों का ध्यान बांटने का चुनावी प्रयास ज्यादा लगता है।

महबूबा मुफ्ती को लेकर उमर अब्दुल्ला का बड़ा हमला

श्रीनगर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार रूहुल्लाह मेहदी के नामांकन भरने पर कहा कि आज उन्होंने नामांकन भरा है। ये कामयाब हों, संसद में बैठकर हमारी मुश्किलों को कम करें और हिंदुस्तान के संविधान की हिवाज़त करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमने इस तरह के चुनाव पहले भी देखे हैं। अब यह बिलकुल साफ है कि ये सब हमारे खिलाफ हैं। भाजपा की तरफ से महबूबा मुफ्ती को समर्थन का ऐलान हुआ है। उनके दो नेताओं ने राजौरी, पुंछ में महबूबा मुफ्ती को समर्थन का ऐलान किया है। भाजपा, उनके तमाम ए,बी,सी टीम, राजभवन सब मिलकर नेशनल कॉन्फ्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की युवा इकाई के अध्यक्ष वहीद रहमान पर्रे ने जम्मू-कश्मीर की श्रीनगर लोकसभा सीट से पर्चा दाखिल किया है, जहां 13 मई को चौथे चरण में मतदान होना है।

नरेंद्र मोदी ने मध्यप्रदेश के मुरैना में विजय संकल्प रैली में कांग्रेस पर साधा निशाना

कांग्रेस ने मां भारती की भुजाएं काट दी, देश के टुकड़े कर दिए: प्रधानमंत्री

भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को मध्य प्रदेश के मुरैना में थे। पीएम मोदी ने यहां पर एक चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि देश के विकास के लिए एक स्थिर और मजबूत सरकार कितनी जरूरी होती है, ये मध्य प्रदेश के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। पीएम ने कहा कि मुरैना ने हमेशा उन्हीं का साथ दिया है, जिनके लिए राष्ट्र प्रथम है। आप सबका उत्साह देखकर मैं कह सकता हूं कि मुरैना आज भी न अपने संकल्प से डिगा है और न ही कभी डिगेगा। मुरैना ने मन बना लिया है-फिर एक बार मोदी सरकार। पीएम ने कहा कि भाजपा सरकार में हुए विकास को भिंड, मुरैना, ग्वालियर के वो लोग और ज्यादा अनुभव कर रहे हैं, जिन्होंने कांग्रेस का काला दौर देखा है। कांग्रेस ने एमपी को बीमारू राज्यों की लाइन में खड़ा कर दिया था।

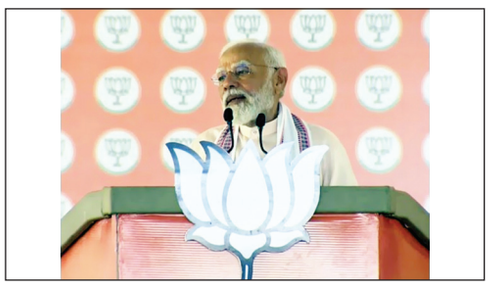

भाजपा की सरकार ने कांग्रेस के बनाए गड्ढों को भरने के बाद मध्य प्रदेश और चंबल को नई और गौरवपूर्ण पहचान दिलाई है। एमपी के लोग जानते हैं कि समस्या से एक बार पीछा छूट जाए, तो फिर उस समस्या से दूर ही रहना चाहिए। पीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ऐसी ही विकास विरोधी और बहुत बड़ी समस्या है। पीएम ने कहा कि 4 जून के बाद हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का विकास और स्पीड पकड़ने जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा के लिए देश से बड़ा और कुछ भी नहीं है। लेकिन, कांग्रेस के लिए अपना परिवार ही सबकुछ है। कांग्रेस की पॉलिसी है, जो देश के लिए सबसे ज्यादा योगदान, मेहनत और समर्पण करे, उसे सबसे पीछे रखो।

उन्होंने कहा कि आजादी के समय कांग्रेस ने धर्म के नाम पर ही देश का बंटवारा स्वीकारा था। मां भारती के हाथों की जंजीरों को काटने की जगह उन्होंने मां भारती की भुजाओं को काट दिया। देश के टुकड़े कर दिए। कांग्रेस आज भी सुधरने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस को अपने लाभ के लिए ये आसान रास्ता लगता है। कुर्सी और सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस छटपटा रही है। कुर्सी पाने के लिए कांग्रेस लगातार खेल खेलने में जुटी हुई है। कांग्रेस ने लंबे वर्षों तक जवानों को उनका हक नहीं दिया। वन रैंक वन पेंशन की मांग को पूरा नहीं होने दिया जो हमने सत्ता में आते ही लागू किया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के लोग जानते हैं कि यह समस्या एक बार पीछे छूट जाए तो फिर समस्या से दूर ही रहना चाहिए। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी ही विकास विरोधी समस्या है, जिसे अब जनता दूर ही रखना चाहेगी। उन्होंने कहा कि हमने सीमा पर खड़े जवानों की सुविधा को भी समझा और जवानों को खुली छूट दी है। कांग्रेस ने जहां जवानों के हाथ बांध रखे थे हमने कहा कि अगर एक गोली आती है तो 10 गोली चलानी चाहिए। एक गोली की जगह 10 तोपें दुश्मन पर वार करनी चाहिए।

पीएम मोदी ने कहा कि इन दिनों कांग्रेस के शहजादे को आए दिन मोदी का अपमान करने में मजा आ रहा है। वो कुछ भी बोलते जा रहे हैं। इससे कुछ लोग दुखी हैं कि देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग क्यों किया जा रहा है। पीएम ने कहा कि मेरी सबसे विनती है कि कृपया करके आप दुखी मत होइए, गुस्सा मत कीजिए, आपको पता है कि वे नामदार हैं और हम कामदार हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि आजकल कांग्रेस के शाही परिवार के शहजादे पूरे देश में बढ़ चढ़कर कह रहे हैं कि अब आपकी संपत्ति का एक्स-रे होगा। हमारी माताओं-बहनों के पास जो पवित्र स्त्रीधन होता है। कांग्रेस उसे जब्त करके अपनी वोटबैंक मजबूत करने के लिए, उसे बांटने की सार्वजनिक घोषणा कर रही है, मेनिफेस्टो में बता रही है। पीएम ने कहा कि आज देश कह रहा है कि कांग्रेस की लूट-जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी।

पीएम ने कहा कि मैं आज देश के सामने पहली बार एक दिलचस्प तथ्य रखना चाहता हूं। जब देश की एक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नहीं रही, तो उनकी जो प्रॉपर्टी थी, वो उनकी संतानों को मिलनी थी। लेकिन पहले ऐसा कानून था कि वो उनको मिलने से पहले सरकार एक हिस्सा ले लेती थी। तब चर्चा थी कि जब इंदिरा नहीं रही और उनके बेटे राजीव गांधी जी को ये प्रॉपर्टी मिलनी थी। तब अपनी उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पहले जो विरासत कानून था, उसको समाप्त कर दिया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एसटी, एससी ओबीसी के हक पर डाका डालने और बहनों के मंगलसूत्र पर नजर डालने से पहले इंडिया गठबंधन वालों दिवार पर लिखा हुआ पढ़ लो और सुन लो कि 'जब तक मोदी जिंदा है तब तक ऐसा कोई भी पाप करने से पहले आपको मोदी से निपटना होगा'। हमारा संकल्प है- जो भी भ्रष्टाचारी हैं उनकी जांच होगी, जिन्होंने गरीबों को लूटा है वह लूट का पैसा गरीबों को वापस मिलेगा। आगरा में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मोदी की गारंटी 'सबका साथ, सबका विकास' की है। लेकिन एसपी-कांग्रेस इंडिया गठबंधन के लिए, उनका वोट बैंक विशेष है। पीएम मोदी ने कहा, चाहे वह हमारे 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हो या भाजपा का घोषणा पत्र हो, हमारा जोर है संतृप्ति पर। कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर किसी को मिले, बिना बिचौलियों के पूरा लाभ मिले। यही भाजपा का संतृप्ति मॉडल है।

पीएम ने लोगों से अपील की है कि मतदान के दिन भारी संख्या में मतदान केंद्र में पहुंचे और वोट करे। गर्मी का मौसम है इसलिए सुबह-सुबह जाकर ही मतदान करे। पीएम ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आपको पिछले जीत के रिकॉर्ड को भी तोड़ना है।

विरासत कर पर भाजपा के बयानों पर जयराम का पलटवार

पीएम मोदी कांग्रेस के घोषणापत्र का कर रहे प्रचार

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के प्रचार के बीच कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा की बुधवार को विरासत कर की बात करके कांग्रेस को एक बार फिर फंसा दिया है। उनके इस बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा लगातार कांग्रेस को घेर रही है। इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी के घोषणापत्र में विरासत कर और धन पुनर्वितरण का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री कांग्रेस के घोषणापत्र का प्रचार कर रहे हैं।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम रमेश ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने देश में विरासत कर को समाप्त किया था। उन्होंने कहा, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारे घोषणापत्र में कहीं भी विरासत कर के बारे में कोई बात नहीं कही गई है। सच्चाई यह है कि 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने विरासत कर को समाप्त किया था। हमने विरासत कर के बारे में कोई जिक्र नहीं किया और यह हमारा एजेंडा नहीं है।

जयराम रमेश ने पीएम मोदी को चुनौती देते हुए कहा, पीएम मोदी कहते हैं कि हमारे घोषणापत्र में धन पुनर्वितरण की बात कही गई है। मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि हमारे 50 पन्नों के घोषणापत्र में कहीं भी धन पुनर्वितरण का जिक्र भी नहीं किया गया है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि पीएम मोदी कांग्रेस के घोषणापत्र को सांप्रदायिक एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, भाजपा मुश्किल में है। प्रधानमंत्री भी हैरान है। 19 अप्रैल के बाद वह पूरे एजेंडा को दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। वे हमारे घोषणापत्र को सांप्रदायिक एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। वह ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं जिसका जिक्र हमारे घोषणापत्र में भी नहीं है।

जयराम रमेश ने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनावी रैलियों में पीएम मोदी हमारे घोषणापत्र का प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने इसे गलत बताया।

उन्होंने आगे कहा कि पहली बार कोई प्रधानमंत्री विपक्ष के घोषणापत्र का प्रचार कर रहा है।

प्रधानमंत्री जानते हैं कि चुनाव उनके हाथ से निकल चुका है : राहुल गांधी

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि उनकी पार्टी की गारंटी और मोदी की गारंटी में फ़र्क साफ़ है तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव उनके हाथ से निकल चुका है।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, कांग्रेस की गारंटी: हिंदुस्तानियों की सरकार, महिलाओं को 8,500 रुपये प्रति माह, युवाओं को एक लाख रुपये प्रति वर्ष की नौकरी, 30 लाख रिक्तियों पर भर्ती और किसानों को कानूनी एमएसपी।

उन्होंने दावा किया, ''मोदी की गारंटी का मतलब अडानियों की सरकार, देश की संपत्ति अरबपतियों की जेब में, चंदे के धंधे वाला वसूली गैंग, संविधान और लोकतंत्र खत्म, किसान पाई-पाई का मोहताज। राहुल गांधी ने कहा कि दोनों गारंटी में फर्क साफ है। कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस हिंदुस्तान में करोड़ों लखपति बनाएगी और मोदी जी जानते हैं कि चुनाव उनके हाथ से निकल गया है।

खेल
प्रमुख समाचार

टी20 विश्व कप: राहुल बनाम संजू में किसका होगा चयन

नईदिल्ली। जून में होने वाले टी20 विश्व कप के लिये भारत की 15 सदस्यीय टीम का ऐलान इस महीने के आखिर में किया जा सकता है लेकिन मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या का खराब फॉर्म चिंता का सबब बना हुआ है जबकि दूसरे विकेटकीपर की जगह के लिये संजू सैमसन से केएल राहुल आगे चल रहे हैं। अमेरिका और वेस्टइंडीज में होने वाले विश्व कप के लिये टीम चुनते समय दुविधा अतिरिक्त गेंदबाज की भी होगी। यह देखना होगा कि तेज गेंदबाज आवेश खान को चुना जाता है या वेस्टइंडीज की धीमी पिचों को देखते हुए लेग स्पिनर रवि बिश्नोई या हरफनमौला अक्षर पटेल को।

समझा जाता है कि कप्तान रोहित शर्मा चयन समिति के प्रमुख अजित अगरकर से मुलाकात कर सकते हैं । आईसीसी ने टीम चुनने के लिये एक मई की समय सीमा दी है। बीसीसीआई इस सप्ताह के आखिर में या अगले सप्ताह की शुरूआत में टीम का ऐलान कर सकता है। पंड्या ने मुंबई इंडियंस के लिये आठ मैचों में 17 ओवर डाले हैं। अभी तक इस आईपीएल में वह सात छक्के ही लगा सकते हैं। उनके बल्ले से 150 रन ही निकले हैं और उनका स्ट्राइक रेट 142 रहा है। वैसे पंड्या के अलावा कोई विकल्प भी नजर नहीं आता क्योंकि शिवम दुबे भी गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। कौशल और रफ्तार के मामले में गेंदबाजी में दुबे कहीं भी पंड्या के समकक्ष नहीं हैं लेकिन बल्लेबाजी में वह शानदार फॉर्म में है जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। आईपीएल में 161 की स्ट्राइक रेट से 342 रन बना चुके विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने अपनी जगह पक्की कर ली है। दूसरे विकेटकीपर के लिये केएल राहुल (141 स्ट्राइक रेट से 302 रन) और संजू सैमसन (152 स्ट्राइक रेट से 314 रन) के बीच मुकाबला है। गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव की जगह लगभग पक्की है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 783 अंक उछला 10 दिनों के हाई पर बंद

नईदिल्ली। भारतीय शेयर बाजार ने गुरुवार को ग्लोबल मार्केट से मिले कमजोर रुझानों को नजरअंदाज कर दिया और शुरुआती गिरावट से स्मार्ट रिकवरी करते हुए 10 दिनों के हाई पर बंद हुआ। उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में आज सेंसेक्स 486 अंक मजूबत हुआ। वहीं निफ्टी में 168 अंक की बढ़त दर्ज की गई। इक्विटी बेंचमार्क सूचकांकों ने गुरुवार के कारोबारी सत्र की शुरुआत नकारात्मक नोट पर की। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 486.50 अंक यानी 0.66 फीसदी की बढ़त के साथ 74,339.44 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज 73,556.15 और 74,571.25 के रेंज में कारोबार हुआ। वहीं, दूसरी तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी 167.95 अंक यानी 0.75 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई। निफ्टी दिन के अंत में 22,570.35 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी में आज 22,305.25 और 22,625.95 के रेंज में कारोबार हुआ।

वोडाफोन-आइडिया का 18000 करोड़ रुपये जुटाना कंपनी में "नई जान फूंकने" जैसा

नईदिल्ली। आदित्य बिड़ला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने गुरुवार को कहा कि वोडाफोन-आइडिया का 18,000 करोड़ रुपये जुटाना कंपनी में "नई जान फूंकने" जैसा है। कंपनी भारी प्रतिस्पर्धा के बीच ग्राहकों को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है। बिड़ला ने एफपीओ के सूचीबद्ध कार्यक्रम में पत्रकारों से कहा कि कंपनी अपने नेटवर्क को बढ़ाने और चुनिंदा 5% सेवाओं को पेश करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। यह पूछे जाने पर कि क्या पूंजी जुटाने से कंपनी की ज्यादातर समस्याएं सुलझ जाएंगी बिड़ला ने "हां" में जवाब दिया। उन्होंने कहा, "यह कंपनी में एक तरह से नई जान फूंकने जैसा होगा।" हालांकि, बिड़ला ने इंडस टावर्स में हिस्सेदारी बेचने की खबरों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

नेस्ले इंडिया का मार्च तिमाही में नेट प्रॉफिट 27 फीसदी बढ़ा

नईदिल्ली। एफएमसीजी सेक्टर की दिग्गज कंपनी नेस्ले इंडिया ने गुरुवार, 25 अप्रैल को अपनी मार्च तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया। मार्च तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 27 फीसदी बढ़कर 934 करोड़ रुपये हो गया। एक साल पहले की समान अवधि में यह 737 करोड़ रुपये था। कंपनी का मुनाफा बाजार के अनुमान से ज्यादा है। बाजार ने 847 करोड़ रुपये के मुनाफे का अनुमान जताया था। शेयर बाजार को दी सूचना में कंपनी ने बताया कि उसका ऑपरेशन से रेवेन्यू 9 फीसदी बढ़कर 5,268 करोड़ रुपये हो गया। एक साल पहले की समान अवधि में यह 4,830 करोड़ रुपये था। बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 8.5 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड की भी सिफारिश की है। नेस्ले इंडिया ने कहा कि लाभ में उछाल का श्रेय कच्चे माल की कीमतों में आई गिरावट को दिया जा सकता है, जो 31 मार्च, 2024 को समाप्त तीन महीनों के लिए 46.4 फीसदी से घटकर 43.3 फीसदी हो गई।

एफएसएसएआई सेरेलैक के नमूने एकत्र कर रहा है: सीईओ

नईदिल्ली। खाद्य सुरक्षा नियामक एफएसएसएआई ने गुरुवार को कहा कि वह नेस्ले के शिशु आहार सेरेलैक के पूरे भारत से नमूने एकत्र कर रहा है। हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि कंपनी उत्पाद में अधिक चीनी डाल रही है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी जी. कमला वर्धन राव ने खाद्य सुदृढ़ीकरण पर एसोचैम के एक कार्यक्रम के मौके पर कहा, "हम देश भर से (नेस्ले के सेरेलैक शिशु आहार के) नमूने एकत्र कर रहे हैं। प्रक्रिया पूरी होने में 15-20 दिन लगेंगे।" भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है।

ईरान-इस्राइल संघर्ष और भारत, बड़ी चुनौती है व्यापार संतुलन

महेंद्र बाबू कुरुवा

बीते 19 अप्रैल को इस खबर के आते ही कि ईरान के इस्फहान शहर के करीब एक प्रमुख एयरबेस के पास एक बड़ा धमाका हुआ है, अमेरिकी अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की कि इस्राइल ने ड्रोन से ईरान में अपना सैन्य अभियान छेड़ दिया है। इससे ऐसा लगता है कि इस्राइल ने रणनीतिक दृष्टि से अपना लक्ष्य चुना है, क्योंकि इस्फहान शहर ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े स्थलों का घर है, जिसमें इसका भूमिगत नतांज संवर्धन स्थल भी है।

पश्चिम एशिया पिछले एक अप्रैल से ही उबल रहा है, जब इस्राइल ने सीरिया स्थित ईरान के दूतावास पर हमला किया था। उसके बाद इस क्षेत्र में भू-राजनीतिक तनाव बढ़ गया है, क्योंकि पहली बार ईरान ने पलटवार करते हुए सीधे इस्राइल पर हमला किया, जिसकी प्रतिक्रिया में इस्राइल ने इस्फहान में ताजा हमला किया है। दोनों धुर विरोधी मुल्कों के बीच दशकों से जो छद्म युद्ध चल रहा था, उसने अब गंभीर मोड़ ले लिया है, जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीतिक स्थिरता के लिए चिंता बढ़ा दी है। भारत पर इस संघर्ष का सबसे बड़ा असर कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के जरिये पड़ेगा। यह इसलिए, क्योंकि भारत कच्चे तेल का दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और पश्चिम एशिया वैश्विक कच्चे तेल के एक-तिहाई का आपूर्तिकर्ता है। ईरान और इस्राइल के बीच तनाव बढ़ते ही आपूर्ति संकट के कारण कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गईं। चूंकि भारत अपनी जरूरत के 85 फीसदी कच्चे तेल की पूर्ति आयात से करता है, इसलिए कीमतों में जरा-सी वृद्धि होने पर भी आयात बिल काफी बढ़ जाता है, जिससे न केवल चालू खाते का घाटा बढ़ता है, बल्कि व्यापार संतुलन भी

बिगड़ जाता है।

दूसरी तरफ, पेट्रोल एवं डीजल की कीमतें बढ़ जाने से परिवहन लागत बढ़ जाती है, जो मुद्रास्फीति बढ़ाती है और आम आदमी का जीवन कठिन हो जाता है। इसके अलावा, तेल की उच्च कीमत और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से डॉलर में मजबूती आएगी, जो भारतीय रुपये को और कमजोर करेगी और देश के समक्ष आर्थिक चुनौतियां बढ़ जाएंगी। इसलिए यदि समय पर इसका प्रबंधन नहीं किया गया, तो इससे देश की व्यापक आर्थिक बुनियादें खतरे में पड़ जाएंगी। यह भी ध्यान देना प्रासंगिक है कि ईरान लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हूती और फलस्तीन में हमास का समर्थन करता है और उनसे सहयोग भी लेता है। ईरान और इस्राइल के बीच तनाव बढ़ने की स्थिति में इस बात की बहुत आशंका है कि ईरान अरब सागर और लाल सागर में व्यापार मार्ग को बाधित करने के लिए हूती विद्रोहियों का सहयोग ले। आशंका इस बात की है कि ईरान दुनिया के सर्वाधिक रणनीतिक महत्व के होर्मूज जलडमरूमध्य को बंद कर सकता है, जो फारस की खाड़ी से खुले महासागर में जाने का एकमात्र समुद्री मार्ग है। यदि ऐसा हुआ, तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो जाएगी, जिससे पूरी दुनिया में मुद्रास्फीति बढ़ने के साथ वैश्विक व्यापार में काफी उथल-पुथल होगा। कहने की जरूरत नहीं है कि भारत को भी बाधित व्यापार प्रवाह और उच्च मुद्रास्फीति और निर्यात क्षेत्र में घाटे का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भारत के इस्राइल और ईरान, दोनों देशों के साथ रणनीतिक हित जुड़े हुए हैं। पिछले दस वर्षों में भारत के संबंध इस्राइल के साथ काफी घनिष्ठ हुए हैं और इस्राइल भारत को आतंकवाद के खिलाफ समर्थन देने के अलावा रक्षा उपकरणों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है।

भारत इस्राइल का एशिया में दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया में सातवां सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। दूसरी तरफ ईरान से भी भारत के पुराने संबंध हैं और इसे ईरान की भी उतनी ही जरूरत है, जितनी इस्राइल की। यह इसलिए कि भारत के मध्य एशियाई देशों, विशेष रूप से कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान आदि जैसे पूर्व सोवियत गणराज्य के राज्यों से रणनीतिक हित और ऐतिहासिक संबंध हैं। इन देशों में बड़े पैमाने पर हाइड्रो कार्बन के भंडार हैं।

तीसरी बार सरकार बनते ही छग के साढे आठ लाख परिवारों को संभालने की जिम्मेदारी भाजपा लेगी

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की केंद्र में तीसरी बार सरकार बनते ही छत्तीसगढ़ के साढे आठ लाख परिवारों को संभालने की जिम्मेदारी भाजपा लेगी। यह श्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और भाजपा का छत्तीसगढ़ के 70 साल के 8.50 लाख से अधिक बुजुर्गों से वादा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार करते हुए उनका पूरा मुफ्त इलाज आयुष्मान कार्ड के जरिए करेगी।

शर्मा ने कहा कि आम नागरिक के इलाज में होने वाली आर्थिक समस्या के लिए आयुष्मान कार्ड प्रारंभ किया और अब इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ते हुए सभी वर्गों के चाहे वह निम्न आय वर्ग हो, मध्यम आय वर्ग हो या उच्च मध्यम आय वर्ग हो, 70 साल व इससे अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक का चिकित्सकीय व्यय वहन करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने ली है। शर्मा ने कहा कि जब एक आम व्यक्ति बीमार पड़ता है तो एक तरफ उसकी आय के साधन रुक जाते हैं और दूसरी तरफ उसके व्यय इस कदर बढ़ जाते हैं कि व्यक्ति समय अनुसार शारीरिक रूप से तो स्वस्थ हो जाता है परंतु वह जीवनभर आर्थिक रूप से बीमार पड़ जाता है और इसीलिए आयुष्मान कार्ड योजना अस्तित्व में आई, जिससे देश के करोड़ों लोगों को इसका लाभ मिला और अब इसका दायरा बढ़ाने की गारंटी प्रधानमंत्री श्री मोदी ने दी है।

आयुष्मान कार्ड से निःशुल्क होगा इलाज

शर्मा ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सलाहकार और कांग्रेस का घोषणापत्र बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले सैम पित्रोदा के विरासत-कर वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और भाजपा ने अपने घोषणापत्र में बुजुर्गों और उनके परिवार को सम्हालने की जिम्मेदारी ली है, वहीं कांग्रेस और इंडी गठबंधन उन बुजुर्गों के मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि वह उनके धन, उनकी सम्पत्ति और विरासत को लूटकर गुलछर्रे उड़ा सकें। श्री शर्मा ने कहा कि पहले अपने घोषणा पत्र में सम्पत्ति का सर्वे करके उन सम्पत्तियों को सबको बाँट देने की बात कही और अब पित्रोदा ने अमेरिकी तर्ज पर विरासत पर मनमाना टैक्स लगाने की बात कहकर कांग्रेस और इंडी गठबंधन की बदनीयती को जगजाहिर कर दिया है। शर्मा ने कटाक्ष किया कि कांग्रेस बबा मार के बरा खाना चाहती है उनकी यह लूट-संस्कृति के खतरनाक मंसूबों को देश की जनता कभी सफल नहीं होने देगी और इस चुनाव में कांग्रेस व इंडी गठबंधन को माकूल जवाब देगी। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल भी उपस्थित थे।

सदर व मालवीय रोड में चारपहिया वाहन बैन

स्मार्ट सिटी के अनेक कार्य अधूरे, जून महीने में कार्यों के लिए आए पैसे लेप्स हो जाएंगे, एमडी नाराज

रायपुर। नगर निगम कमिश्नर अबिनाश मिश्रा ने बुधवार की देर शाम अधिकारियों की बैठक ली, इस दौरान उन्होंने जोन क्रमांक 2, 4 और 7 में स्मार्ट सिटी के अधूरे कार्यों को लेकर नाखुश नजर आए और अधिकारियों से कहा कि जून महीने में स्मार्ट सिटी के कार्यों के लिए आए पैसे लेप्स हो जाएंगे इसलिए जल्द से जल्द कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। निगमायुक्त ने सदर और मालवीय रोड में चार पहिया वाहनों को बैन करने के निर्देश दिए। निगम मुख्यालय भवन में कल देर शाम नगर निगम आयुक्त मिश्रा ने स्मार्ट सिटी के अधिकारियों की बैठक ली। जिसमें निगम के अधीक्षण अभियंता राजेश शर्मा, स्मार्ट सिटी के उप प्रबंधक पी के पंचायती, जोन क्रमांक 6 के कार्यपालन अभियंता अतुल चोपड़ा तथा स्मार्ट सिटी में पूर्व के कार्य कर चुके उप अभियंता अंशुल शर्मा

समेत स्मार्ट सिटी के अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में श्री मिश्रा ने कहा कि जोन क्रमांक 2, 4 और 7 में बहुत सारे कार्य अधूरे हैं। वहां कई ऐसे भी कार्य भी जिनके कर देने से उन जगहों की दशा बदल जाएगी और वह जगह सुंदर दिखने लगेगी। बूढ़ापारा के धरनास्थल के सौंदर्याकरण और महराज बन्ध तालाब फेस 2 के तथा अन्य कार्यों की उन्होंने समीक्षा की। जून महीने में स्मार्ट सिटी के कार्यों के लिए आए पैसे लेप्स हो जाएंगे। इस पर उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्य के पैसे लेप्स ना, इसलिए जल्द से जल्द सारे कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित किया। किसी कार्य के लिए भारत सरकार से यदि 50 लाख रुपए की स्वीकृत मिल कर उसे कार्य की किस्त 20 लाख मिल गई हो तो उस कार्य को पूर्ण कर बाकी रकम प्राप्त करने हेतु कार्यवाई की जाए। निगम के जोन क्रमांक 2,4 और 7 में स्मार्ट सिटी के द्वारा किये जा रहे कार्यों से एमडी अबिनाश मिश्रा नाखुश दिखे। उन्होंने इन जगहों के साथ ही बाकी जगहों के कार्य तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

मोदी सरकार ने 70 वर्ष से ऊपर आयु के बुजुर्गों को स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित क्यों रखा?

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा की भाजपा को चुनाव में हार नजर आ रही है इसलिए अब उन्हें बुजुर्गों की याद आ रही हैं अब बुजुर्गों को स्वास्थ्य सुविधा देने का दावा कर फॉर्म भरवा रही हैं। देश के करोड़ों बुजुर्ग भाजपा के इस चरित्र को देख चुके हैं। अब बुजुर्ग भी भाजपा के खिलाफ मतदान करेंगे और उनके साथ हुए अन्याय धोखा का बदला लेंगे। भाजपा को बताना चाहिए कि मोदी सरकार ने 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को स्वास्थ्य की सुविधाओं से वंचित क्यों रखा है? ट्रेन में यात्रा के दौरान बुजुर्गों को मिलने वाली सब्सिडी को खत्म कर दिया गया? कई सारी सुविधाये 2014 के पहले दी जा रही थी वह सारी सुविधाएं भी खत्म कर दी गई है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार युवाओ, बुजुर्गों, किसान, महिला, मजदूर, के लिये कोई काम नहीं किया हैं। जब चुनाव आते हैं तब भाजपा फॉर्म भराने की नाटक और नौटंकी करती हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान भी 80 लाख से अधिक महिलाओं से फार्म भरवाया गया था और मात्र 30 प्रतिशत महिलाओं को ही महतारी वंदन योजना का पैसा मिला है।

दिव्यांगजन, नवविवाहिता, बुजुर्ग मतदाताओं का किया सम्मान

रायपुर। ज़िला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह की उपस्थिति में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत विधानसभा आरंग अंतर्गत, नगर पंचायत समोदा में रैली, दीपदान, अकाशदीप के साथ ही उपस्थित गणमान्य नागरिकों को बैच लगाकर मतदाता शपथ दिलाकर शत प्रतिशत मतदान करने की अपील की गयी। कार्यक्रम में दिव्यांगजन, नवविवाहिता,85 वर्ष आयु के मतदाताओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान आरंग अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) श्री पुष्पेन्द्र शर्मा, तहसीलदार श्री राजकुमार साहू, श्रीमती सीता शुक्ला, श्रीमती श्रुति शर्मा सहित गणमान्य नागरिक गण उपस्थित थे। उल्लेखनीय है रायपुर लोकसभा में मतदान आगामी 7 मई को है।

आईपीएल में सट्टा खिलाने वाले 8 सटोरिए गोवा से गिरफ्तार

रायपुर। आईपीएल क्रिकेट मैच के दौरान सट्टा संचालित करते 5 अंतर्राज्यीय सहित कुल 8 सटोरियों को एंटी क्राइम एंड सायबर यूनिट और गंज पुलिस ने धर दबोचा है. ये आरोपी गोवा में बैठकर एमडी 143 आईडी से आईपीएल क्रिकेट मैच में सट्टे का संचालन कर रहे थे. ये सटोरिए 25 लाख रुपए में एमडी 143 आईडी लिए थे. सटोरियों के कब्जे से 4 नग लैपटॉप, 01 नग कैमरा, 01 नग कैल्क्युलेटर, 27 नग मोबाइल फोन, 1 राउटर एवं लिंक कनेक्टर जुमला कीमती लगभग 10,00,000 रुपए और 11 नग एटीएम कार्ड एवं 1 चेक बुक जब्त किया गया है. सटोरियों के पास जब्त मोबाइल फोन में लगभग 10 करोड़ों रुपए के लेन-देन की जानकारी प्राप्त हुई है. सटोरियों के विरूद्ध गंज थाने में अपराध दर्ज कर सभी को जेल भेज दिया गया है. इस मामले में जय, करण एवं मोहित नामक सटोरियों की संलिप्तता के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है, जिनकी पतासाजी में पुलिस जुटी है. 22 अप्रैल को एण्टी क्राइम एण्ड सायबर यूनिट टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना गंज क्षेत्रांतर्गत स्थित रेलवे स्टेशन पास एक व्यक्ति अपने मोबाइल फोन में आईपीएल क्रिकेट मैच के दौरान ऑनलाइन सट्टा खेल रहा है. जिस पर वरिष्ठ अधिकारों के निर्देश के बाद एण्टी क्राइम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना गंज पुलिस की संयुक्त टीम ने उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताए हुलिये के व्यक्ति को चिन्हांकित कर पकड़ा.

यह चुनाव संविधान और लोकतंत्र बचाने का चुनाव

रायपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं प्रदेश प्रभारी डॉ. चंदन यादव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुये कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को चेतावनी दे रहा हूं कि संविधान जिंदाबाद था, संविधान जिंदाबाद है, और संविधान जिंदाबाद रहेगा। 2024 का लोकसभा चुनाव सिर्फ सत्ता का परिवर्तन का चुनाव नहीं है, दो विचारधारा का चुनाव है। संविधान बचाने का चुनाव है और देश को बनाने और बचाने का चुनाव है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जिस नीयत और नीति से 400 पार का नारा दिया था, अब वो जनता के बीच आ गया है कि उसका मतलब क्या है? कही जमीन पर कोई हकीकत नहीं था 400 से नीचे जा रहे है। जैसे-जैसे चुनाव चढ़ता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी उसी तेज रफ्तार से नीचे जा रही है। 400 पार का क्या मतलब होता है कई बड़े नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा वो संविधान बदलना चाहते है। जब जनता को बात समझ आ गया तब भारतीय जनता पार्टी के नेता सफाई दे रहे है। लेकिन वो सफाई सच्चाई से परे है। भाजपा ने पहली बार ऐसा नहीं किया है, जब पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी तब बाजपेयी की सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमेटी बनाया था। जिसके अध्यक्ष जस्टिस वेंकटेश चिलैय्या थे। जब-जब भाजपा की सरकार बनी है तब-तब वो संविधान में छेड़छाड़ बदलने का प्रयास करते रहे है। मैं इस देश की जनता को नमन करता हूं। देश और देश की जनता संविधान का जिंदाबाद का नारा इस देश के कण-कण में बसा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो मूल विचारधारा है और देश का संविधान है वे परस्पर विपरीत है। आरएसएस का विचारधारा है और हमारा संविधान कहता है आजादी के संघर्षो दौरान जो उत्पन्न हुई वो इस देश का संविधान है। देश की जनता के संघर्षो से उत्पन्न बहुत सारे हमारे परंपरा, इतिहास, स्टेटजी, सबसे बड़ा अहिंसा, तमाम ऐसे मूल्य है और तमाम हमारे बड़े-बड़े नेताओं का बहुत बड़ा संघर्ष रहा है। डॉ. बाबा साहब अंबेडकर राष्ट्रीय कमेटी के चेयरमेन रहे, तमाम ऐसे नेता थे सभी ने मिलकर ये एक बहुत ही मजबूत संविधान बनाया है। जो भारतीयता को दर्शाता है। भारत बोले तो अनेकता में एकता है। भारत को समझना चाहेंगे तो 22 प्रमुख भाषाएं है, 1632 बोली है, 6500 जाति-उपजाति है, 52 जनजातियां है, 29 मुख्य त्योहार है, 6 मुख्य धर्म है, 27 राज्य है, 7 केंद्र शासित प्रदेश है.

जग्गी हत्याकांड, सरेंडर करने अभय को सुको से मिली 6 सप्ताह की मोहलत

रायपुर। सुप्रीम कोर्ट ने रामअवतार जग्गी हत्याकांड के एक अन्य आरोपी अभय गोयल को कोर्ट में सरेंडर करने 6 सप्ताह की मोहलत दे दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के सरेंडर करने के आदेश पर सभी 6 आरोपियों को सरेंडर करने की राहत दी। सुप्रीम कोर्ट से अभय गोयल को सरेंडर करने के लिए 6 हफ्ते का वक्त मिला 06 हफ्ते बाद अभय गोयल को रायपुर के एस्ट्रोसिटी कोर्ट में सरेंडर करना होगा। इससे पहले सजा पाने वाले 5 अभियुक्त याहया ढेबर और सूर्यकांत तिवारी के अलावा तात्कालीन कोतवाली सीएसपी अमरीक सिंह गिल, मौदहापारा टीआई वीके पांडे और क्राइम ब्रांच प्रभारी उपनिरीक्षक आरसी त्रिवेदी को सुप्रीम कोर्ट से सरेंडर के लिए तीन हफ्ते का समय मिला है। सेशन कोर्ट ने जग्गी हत्याकांड के 28 आरोपियों को सजा सुनाई थी। इस सजा के खिलाफ अभियुक्तों की तरफ से अलग-अलग याचिकाएं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट मे दायर की गई थीं। अलग-अलग मामलों में सुनवाई के बाद 29 फरवरी को सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिए गया था। बाद में इसमें आदेश हुआ, जिसमें हाईकोर्ट ने निचले अदालत कोर्ट की सजा को बरकरार रखा और एक हफ्ते में सभी अभियुक्तों को सरेंडर करने को कहा गया था। इसके बाद पांच लोगों ने याचिकाएं लगाईं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने तीन पुलिस अफसरों सहित 5 अभियुक्तों को तीन हफ्ते का वक्त दिया।

संविधान जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा - यादव

यह चुनाव संविधान बचाने, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है

रायपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं प्रदेश प्रभारी डॉ. चंदन यादव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुये कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को चेतावनी दे रहा हूं कि संविधान जिंदाबाद था, संविधान जिंदाबाद है, और संविधान जिंदाबाद रहेगा। 2024 का लोकसभा चुनाव सिर्फ सत्ता का परिवर्तन का चुनाव नहीं है, दो विचारधारा का चुनाव है। संविधान बचाने का चुनाव है और देश को बनाने और बचाने का चुनाव है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जिस नीयत और नीति से 400 पार का नारा दिया था, अब वो जनता के बीच आ गया है कि उसका मतलब क्या है? कही जमीन पर कोई हकीकत नहीं था 400 से नीचे जा रहे है। जैसे-जैसे चुनाव चढ़ता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी उसी तेज रफ्तार से नीचे जा रही है। 400 पार का क्या मतलब होता है कई बड़े नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा वो संविधान बदलना चाहते है। जब जनता को बात समझ आ गया तब भारतीय जनता पार्टी के नेता सफाई दे रहे है। लेकिन वो सफाई सच्चाई से परे है। भाजपा ने पहली बार ऐसा नहीं किया है, जब पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी तब बाजपेयी की सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमेटी बनाया था। जिसके अध्यक्ष जस्टिस वेंकटेश चिलैय्या थे। जब-जब भाजपा की सरकार बनी है तब-तब वो संविधान में छेड़छाड़ बदलने का प्रयास करते रहे है। मैं इस देश की जनता को नमन करता हूं। देश और देश की जनता संविधान का जिंदाबाद का नारा इस देश के कण-कण में बसा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी

आपदा प्रबंधन की मिसाल बनी बिजली भंडार की आगजनी

उपलब्ध संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल व समन्वय से शीघ्र रोकथाम ,जनहानि,जनसंपत्ति हानि का बचाव

रायपुर। एक कहावत है जान है तो जहान है लेकिन यह समय की शिला पर उकेरा गया सबसे बड़ा सच भी है। दुनियाभर में जितने भी कर्म किये जाते हैं, उनमें सबसे बड़ा काम वही माना जाता है, जो किसी की जान बचाने के लिए किया गया हो। 05 अप्रैल 2024 को छत्तीसगढ़ की राजधानी, रायपुर के आसमान पर जो काले धुंये का गुबार छाया था, वह सारे शहर में दहशत फैला रहा था कि पता नहीं कितनों की जान और माल पर कितना खतरा मंडरा रहा है? आग के बारे में कहा जाता है कि वह पानी से बुझती है लेकिन तेल की आग पर पानी भी बेअसर होता है, तो सवाल उठता है कि ऐसी आग कैसे बुझेगी ? अब इस आग की विकरालता के साथ जुड़ी अन्य चुनौतियों पर भी गौर करना जरूरी है।

घनी बस्ती व ऑयल से भरे डिब्बा बन्द- एक ओर 132 के.वी. क्षमता का विद्युत उपकेंद्र और दूसरी ओर घनी बस्ती। उस घनी बस्ती और भभकती ज्वाला के बीच ऑयल से भरे हुए डिब्बाबंद ड्रम। एक छोटी सी बोतल में भरा पेट्रोल कितना विध्वंसक होता है, यह सब को पता है, तो ऑयल भरा हुआ डिब्बाबंद ड्रम कितना कहर ढा सकता है?

दूसरों की जान की परवाह करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य- यह सोचकर भी आत्मा कांप उठे। वह पर ऐसा एक नहीं, अनेक ड्रम थे। इन ड्रमों को वहां से हटा देना ही भयानक शक्तिशाली बमों को डिफ्यूज करने जैसा राहतकारी कदम था। थोड़ी ही दूरी पर, खुले मैदान पर पड़े ऑयल भरे ट्रांसफार्मर बमों की तरह फट रहे थे और उससे थोड़ी दूर ऑयल के ड्रमों को हटाने के लिए अपनी जान की बाजी वही लगा सकता है, जो दूसरों की जान की परवाह करता हो और जान बचाने को ही सबसे बड़ा कर्तव्य समझता हो।

अधिकारियों के फर्ज तो औरो के लिए प्रेरणा- ऐसे कुछ वीडियोज वायरल हुए हैं, जिसमें एक महिला और कुछ पुरुष अधिकारी स्वयं ऑयल भरे ड्रमों को धकेलकर आग की जद से दूर ले जाते दिख रहे हैं। जैसे कि युद्ध जैसी बमबारी और धमाकों के बीच भी उन्हें सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही हो , बचाव, बचाव, बचाव। इनके साहस और जज्बे को सलाम करने के बजाय जो लोग दूरबीन लेकर लापरवाही ढूंढ रहे हैं, उनसे कुछ कहना निरर्थक है।

जाहिर है कि ऐसे हालातों के बीच वही व्यक्ति काम कर पाता है, जो यह जानता हो कि प्रिवेंटिव मेन्टेनेन्स की अपनी अहमियत तो है ही, लेकिन जब कोई आपदा आ ही गई हो तो उससे निपटने का हर संभव और श्रेष्ठतम प्रबंधन ही सर्वश्रेष्ठ रास्ता होता है। आपदा प्रबंधन का सबसे बड़ा सिद्धांत है, न्यूनतम क्षति के साथ संकट से निजात।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.